BJYM Magazine

JAN 2025 VOL 40

DELHI DESERVES BETTER

HOLDING AAP ACCOUNTABLE

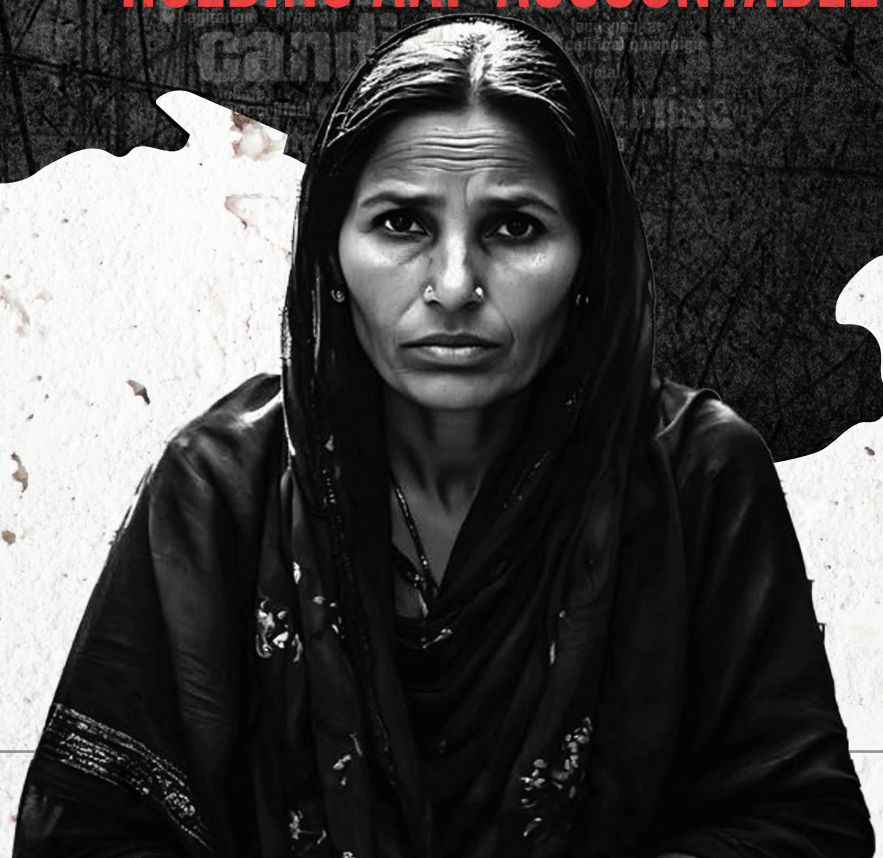

CONTENTS

01 दिल्ली में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखने और उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन

05 भाजपा अध्यक्ष श्री जे. पी. नड्डा की टिप्पणी

06 Message from the BJYM National President Shri Tejasvi Surya

07 Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

Abhinav Prakash
National Vice-President, BJYM

ADVISORY BOARD

Varun Jhaveri
National In-charge Policy and Research, BJYM

Kapil Parmar
National Head Social Media & IT

EDITORIAL BOARD

Rahul Bhaskar
Adarsh Tiwari
Ragini Kapoor
Saurabh Kumar Pandey
Dr. Mrittunjoy Guha Majumdar
Kunal Tilak
Mutum Yoiremba

MAGAZINE TEAM

Dhananjay Sharma
Pranit Gupta

AVAILABLE ON

BJYM website:
https://bjym.org/

BJP E-Library:
http://library.bjp.org/jspui/handle/123456789/3082

09 Hype over Substance: A Decade of Disappointment under AAP
- Shehzad Poonawalla

12 Punjab in Crisis: Broken Promises and Governance Failures under AAP
- Amandeep Singh

14 The Financial Mismanagement of AAP: A Decade of Economic Decline in Delhi
- Vishu Basoya

16 Populysis and Freebruption
- Dr. Mrittunjoy Guha Majumdar

20 Toxic Legacy: Environmental Degradation under AAP
- Sushant Mehlawat

22 भ्रष्टाचार, अपराध और वादाखिलाफी: आम आदमी पार्टी के शासन का सच
- डॉ. वृंदा काल्हेर

25 Debt, Denial, and Decline: Punjab under AAP
- Lakshit Mittal

27 झूठे वादों की राजनीति: केजरीवाल का मॉडल बेनकाब
- चन्दन कुमार

29 Grandstanding over Governance: Failed Model of AAP
- Bharat Sharma

31 आम आदमी पार्टी विफल जल प्रबंधन: क्या कहते हैं आंकड़े?
- विश्वजीत पाठक

33 Populism vs. Progress: Evaluating BJP and AAP on Development Metrics
- Sagar Saikia

37 केजरीवाल सरकार: झूठे वादों और विफल योजनाओं का दशक
- मनुजम कुमार

40 The Tragicomedy of Education: From Delhi Model to Punjab Mess
- Vaibhav Singh Rathore

42 City Beautiful in Decline: AAP's Failed Governance in Chandigarh
- Vaibhav Gupta

44 Governance on Trial: The Nexus of Crime, Drugs, and Mismanagement under AAP
- Abhinav Koli

46 AAP Governance Model: False Promises and Flawed Delivery
- Tirthankar Jana

48 A Cautionary Tale: How AAP's Policies Undermine Delhi's Future
- Pranjal Chaturvedi

51 झूठे वादे और झूठे प्रचार का केजरीवाल मॉडल
- अरुण राठी

दिल्ली में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखने और उद्घाटन के अवसर पर **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन**

आप सभी को, साल 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। साल 2025, भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज़ होने वाली है। आज भारत, दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा, ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैनुफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा, ये वर्ष, युवाओं को नए स्टार्टअप और आंत्रप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा, ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष वूमन लेड डवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा, ये वर्ष Ease of Living बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है।

आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर हैं, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं-बहनों को बधाई देता हूं, जिनकी एक तरह से अब नई ज़िंदगी शुरु हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है। ये आत्मसम्मान का घर है। ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी, उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे। और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुराने यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है।

आज पूरा देश, विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में, देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हों, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई-बहनों के लिए 3 हज़ार से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रहीं, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और डेढ़ हजार घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये "स्वाभिमान अपार्टमेंट्स", गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई, तो मैं यही ऐहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। और वहां मुझे कुछ बालक-बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला, ऐसा लग रहा था कि स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना उससे भी ऊंचे उनके सपने मैं देख रहा था। इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग-अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं।

देश भली-भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले और अभी भी जो लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं, वादा करके आना आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है, जो बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3 हज़ार ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हज़ारों नए घर, दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई-बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे, वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही, केंद्र सरकार, रोहिणी और द्वारका सब-सिटी के बाद, अब नरेला सब-सिटी के निर्माण को गति दे रही है।

विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका, हमारे शहरों की है। हमारे ये शहर ही हैं, जहां दूर-दूर से लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, पूरी ईमानदारी से उन सपनों को पूरा करने में जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए, केंद्र की भाजपा सरकार, हमारे शहरों में रहने वाले हर परिवार को क्वालिटी लाइफ देने में जुटी है। हमारा प्रयास है कि गरीब हो या मिडिल क्लास, उसको अच्छा घर दिलाने में मदद मिले। जो नए-नए लोग गांव से शहर आए हैं, उन्हें उचित किराए पर घर मिले। जो मध्यमवर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास है उसको भी अपना सपनों का घर पूरा करने के लिए सरकार पूरी मदद दे रही है। बीते एक दशक से ये काम लगातार, ये काम निरंतर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इसके तहत देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। इसी योजना के तहत दिल्ली में भी करीब 30 हज़ार नए घर बने हैं।

अब इस प्रयास को हमने और विस्तार देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अगले चरण में, शहरी गरीबों के लिए एक करोड़ नए घर बनने वाले हैं। इन घरों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ही मदद देने वाली है। साल में जिनकी आय 9 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों को इस योजना का विशेष फायदा होगा। केंद्र सरकार मिडिल क्लास परिवारों को, मध्यमवर्गीय परिवारों का घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन के ब्याज में बहुत बड़ी छूट दे रही है, वो पैसे सरकार दे रही है।

हर परिवार का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और अपने पैरों पर खड़े हों। देश में अच्छे स्कूल-कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, अच्छे प्रोफेशनल संस्थान हों, इस पर भाजपा सरकार द्वारा बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी करना है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात का ध्यान रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गरीब परिवार को बच्चा हो, मध्यम परिवार की संतान हो उनको नए अवसर देने वाली नीति को लेकर चलता है। हमारे देश में मध्यमवर्ग परिवार के बच्चे हो, गरीब परिवारों के बच्चे हो, उनके लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ी अदालत में खड़े होकर के वकालत

करना, ये सारे सपने उनके भी होते हैं। लेकिन मध्यमवर्ग के परिवार के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है। गरीब के लिए बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देना मुश्किल होता है। अगर मेरे मध्यमवर्ग के बच्चे, मेरे गरीब परिवार के बच्चे, क्या अंग्रेजी के अभाव में डॉक्टर-इंजीनियर नहीं बन सकते हैं क्या? उनका डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए आजादी के इतने सालों तक काम नहीं हुआ, वो आपके इस सेवक ने कर दिया है। अब वो अपनी मातृभाषा में पढ़कर के डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है और बड़ी से बड़ी अदालत में मुकदमा भी लड़ सकता है।

देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में CBSE की बड़ी भूमिका है। इसका दायरा निरंतर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए ही, CBSE का नया भवन बनाया है। इससे आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में, परीक्षा के आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी।

उच्च शिक्षा के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भी लगातार मजबूत हो रही है। और ये मेरा सौभाग्य है मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य मिला। हमारा प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को यहीं पर उच्च शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलें। आज जिन नए परिसरों का शिलान्यास किया गया है, इससे हर वर्ष सैकड़ों नए साथियों को डीयू में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। डीयू के पूर्वी कैंपस और पश्चिमी कैंपस का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। अब ये इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेज़ी से काम होगा। वहीं नज़फगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है।

एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से हैं, उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिये ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों की भविष्य की परवाह नहीं है, जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिये, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए ये लोग।

ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है। सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली, एक बड़ी, दिल्ली, एक बड़ी आप-दा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आप-दा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला, ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग 'आप-दा' बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसका महिमामंडन भी करते हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, ये, ये आप, ये आप-दा दिल्ली पर आई है। और इसलिए, दिल्ली वालों ने आप-दा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर, दिल्ली को आप-दा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है- आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आप-दा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।

दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के ज़िम्मे हैं। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े-बड़े अस्पताल, बड़े-बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आप-दा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है, उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आप-दा ने घेर रखा है, उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आप-दा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी हैं, यमुना नदी। अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे, तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही? उन्होंने कहा साहब, सर पर हाथ जोड़कर कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा-मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्लीवासी को यमुना जी की ये स्थिति।

आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं और बेशर्मी देखो लाज-शर्म का नामोनिशान नहीं, ये कैसी आप-दा, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे, वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आप-दा ने, दिल्लीवालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आप-दा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे।

मेरा ये निरंतर प्रयास है कि देश के लिए जो भी अच्छी योजनाएं बन रही हैं, उनका लाभ मेरे दिल्ली के भाई-बहनों को भी मिले। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं भी मिल रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं।

केंद्र की भाजपा सरकार, बिजली का बिल ज़ीरो कर रही है और इतना ही नहीं बिजली से कमाई के अवसर भी दे रही है। पीएम सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना से, हर परिवार आज बिजली उत्पादक बन रहा है। भाजपा सरकार, हर इच्छुक परिवार को 78 हजार रुपये, करीब-करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रूपए दे रही है। अभी तक, देशभर में करीब साढ़े 7 लाख घरों की छत पर पैनल लग चुके हैं। इससे ज़रूरत की बिजली मुफ्त मिलेगी और बची हुई बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास

दिलाता हूं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू की जाएगी।

आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को, भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था। पुराने अखबार निकालकर देखिए क्या-क्या होता था। आप-दा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है।

दिल्ली के गरीब हों, मध्यम वर्गीय परिवार हों, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जनऔषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 80 परसेंट से अधिक डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध हैं, 100 रूपए की दवाई 15 रूपए, 20 रूपए में मिलती है। इन सस्ती दवाओं से दिल्ली के लोगों को हर महीने हज़ारों रुपए की बचत हो रही है।
मैं तो दिल्लीवालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं। लेकिन आप-दा सरकार को दिल्लीवालों से बड़ी दुश्मनी है। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आप-दा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल्ली के व्यापारी देशभर में जाते-आते रहते हैं, दिल्ली के प्रोफेशनल देशभर में जाते-आते रहते हैं, दिल्ली के नौजवान देशभर में जाते-आते रहते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में गए और कुछ हो गया अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपके ट्रीटमेंट के गारंटी बन जाएगा। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली की आप-दा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है ये आपदा के पाप के कारण।

भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। किसी भी परिवार का 70 साल के ऊपर का व्यक्ति, अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी ही सेवा करना चाहे, लेकिन आप-दा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है, फायदा नहीं ले पा रहे हैं। आप-दा वालों का स्वार्थ, आप-दा वालों की ज़िद्द, आप-दा वालों का अहंकार, आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं।

दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की, लेकिन यहां की आप-दा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आप-दा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आप-दा सरकार, इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की, सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही हैं। इसके चलते, लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हों, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कसमें खाके, अपने लिए शीशमहल बनवा लेते हैं, उनसे जब ये आप-दा जाएगी और भाजपा आएगी, तो इन सारी समस्याओं का भी समाधान भी किया जाएगा।

आपको याद रखना है जहां-जहां आप-दा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। आपके सामने DDA-दिल्ली डवलपमेंट अथॉरिटी का उदाहरण है। DDA में आप-दा का उतना दखल नहीं है। इसके कारण, DDA गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नए घर बना पा रही है। दिल्ली के हर घर तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेज़ी से चल रहा है। ये काम भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें भी आप-दा की दखल नहीं है। दिल्ली में इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये भी इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि इसमें आप-दा की दखल नहीं है।

आप-दा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा, दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। दो दिन पहले ही हमारे दिल्ली के सातों एमपी, हमारे सांसदों ने यहां की ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए अहम सुझाव भारत सरकार को दिए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाना हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को K.M.P एक्सप्रेसवे से जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड– टू से जोड़ना हो, या दिल्ली का ईस्टर्न बाईपास हो, ये हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए हैं इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है, इन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनसे आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा।

साल 2025, दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। ये साल, राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, मेरे लिए दिल्ली वासी प्रथम इस भाव को सशक्त करेगा। ये साल, दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जनकल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा। और इसलिए, आप-दा को हटाना है, भाजपा को लाना है, आप-दा को हटाना है, भाजपा को लाना है, आप-दा को हटाना है, भाजपा को लाना है, आप-दा को हटाना है, भाजपा को लाना है। इसी विश्वास के साथ, आप सभी को नए घरों के लिए, नए शिक्षा संस्थानों के लिए फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई।

Source: pmindia.gov.in

भाजपा अध्यक्ष **श्री जे. पी. नड्डा** की टिप्पणी

दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव झूठ एवं भ्रष्टाचार रूपी अरविंद केजरीवाल और सच एवं विकास रूपी भाजपा के बीच चुनाव का अवसर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल रूपी आप-दा से मुक्त होने का मन बना लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की महान जनता इस चुनाव में सच एवं विकास को चुनेगी और दिल्ली को आप-दा से मुक्त करवाएगी।

Source: BJP.ORG

Message from the BJYM National President **Shri Tejasvi Surya**

The Aam Aadmi Party (AAP) came to power promising revolutionary governance, corruption-free administration, and transformative policies in Delhi and Punjab. However, after a decade in Delhi and nearly two years in Punjab, the so-called "Kejriwal model" has proven to be nothing but a façade. From mismanaged public services to rampant corruption and policy failures, AAP has turned its promises into hollow rhetoric. Whether it's the crumbling healthcare infrastructure, a faltering education model, or Delhi's infamous water and pollution crises, AAP has failed the people at every step. It is time to dismantle this illusion and put our faith in a party that delivers—BJP.

AAP has become synonymous with corruption and chaos. From the Delhi liquor scam to the sand mafia in Punjab, AAP leaders have been embroiled in one scandal after another. The party that promised to cleanse politics has itself become a cesspool of criminal activities, with several leaders facing serious allegations. In Punjab, under Bhagwant Mann's government, gangsters thrive, and law and order have crumbled. This is not governance; this is a betrayal of the Aam Aadmi.

In stark contrast, BJP's double-engine governments—one at the centre and another in the state—has proven to be a successful model for development and growth. States like Uttar Pradesh, Haryana and Gujarat have demonstrated the benefits of alignment between state and central governments. From large-scale infrastructure projects to pro-poor welfare schemes like Ayushman Bharat and Jal Jeevan Mission, BJP has ensured that development reaches every citizen. Imagine how much more Delhi could achieve with a double-engine government led by the BJP! It's time to align Delhi with the centre and accelerate its development.

While AAP has made lofty promises without delivering, BJP has consistently delivered on its commitments. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, central schemes like PM-KISAN, Ujjwala Yojana, and PM-SHRI have transformed lives across the country. In contrast, AAP has blocked central schemes in Delhi, depriving citizens of their benefits. Punjab's farmers were promised relief during the elections, yet their issues remain unresolved. The people deserve a party that respects their mandate and fulfils its promises—not one that thrives on advertisements and excuses.

The upcoming election is not just about choosing a government—it is about choosing the future of Delhi. Do we want a government that prioritises propaganda over progress or one that is committed to real development and empowerment? I urge every voter to reject the deceitful politics of AAP and embrace the BJP's vision of a prosperous and strong India. Let's give Delhi the double-engine power it needs to thrive. It's time to vote for accountability, progress, and integrity. Vote for BJP!

Vande Mataram!

Tejasvi Surya

MP Lok Sabha,
Bengaluru South

EDITORIAL

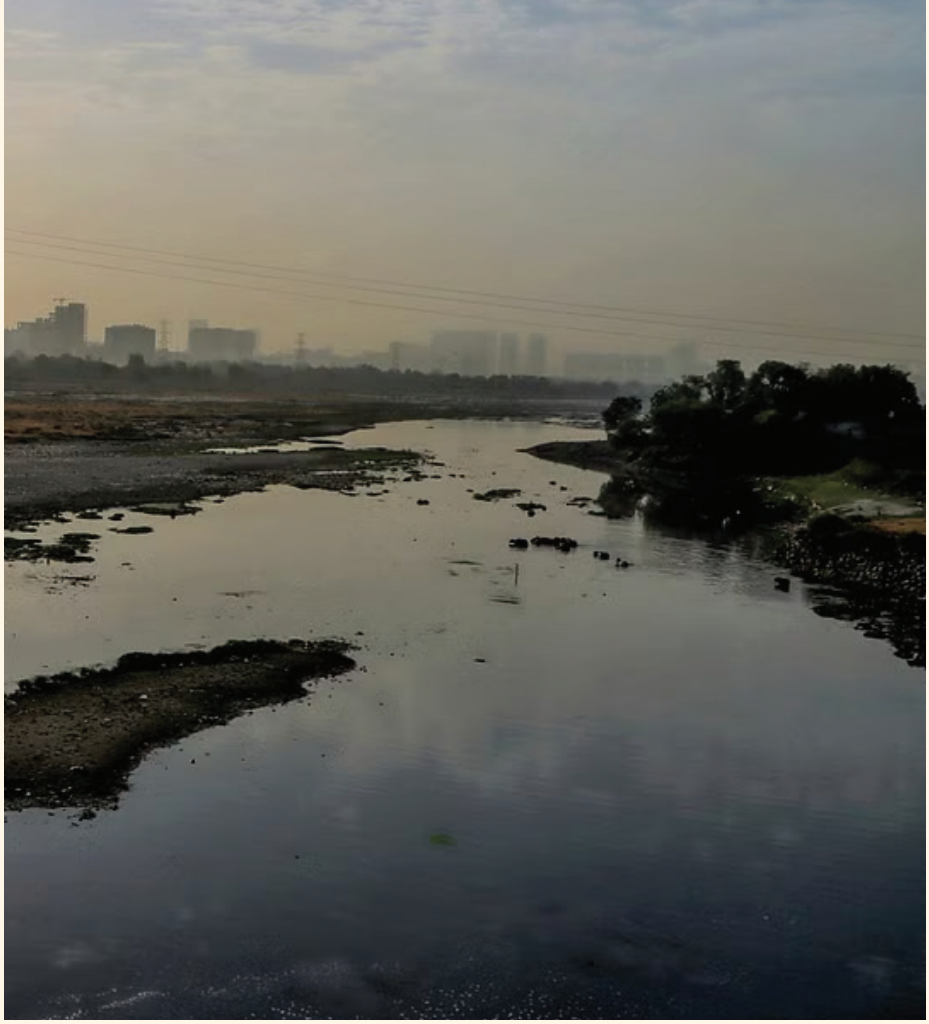

Delhi, the beating heart of India, has long embodied the nation's vibrant diversity and unbridled aspirations. Yet over the past decade, these aspirations have been chipped away by a government that rose to power on a wave of optimism but always prioritised spectacle over substance. When the Aam Aadmi Party (AAP) first burst onto the scene, it promised a clean administration and a revolutionary overhaul of everyday life. The reality, however, has been nothing short of disastrous.

Consider the city's water crisis. Despite lofty pledges of uninterrupted supply, many neighbourhoods remain reliant on tanker mafias to secure a resource as essential as drinking water. AAP's much-publicised expenditure of ₹6,856 crore on cleaning the Yamuna has failed to yield any substantial improvement, with the river still among the nation's most polluted. These failures are emblematic of an administration that seems adept at making promises yet struggles to deliver.

Education, once a flagship issue for AAP, presents an equally distressing picture. The government touts its "model schools" in glossy promotional campaigns, but walk beyond these showcases, and a starkly different reality emerges: thousands of vacancies remain unfilled, and many schools lack usable toilets, clean drinking water, or basic teaching materials. Particularly concerning is the practice of shifting underperforming students to open schools, a tactic that artificially bolsters pass percentages while sacrificing genuine reform.

The overarching impression is that optics frequently displace meaningful progress. A similar pattern is evident in healthcare. The "Mohalla Clinics," initially lauded as a transformative innovation, are often short-staffed, poorly stocked with medicines, and ill-equipped to serve their communities. Meanwhile, major government hospitals buckle under the weight of demand, their corridors packed with patients competing for scarce beds. The COVID-19 crisis laid bare how ill-prepared the city's healthcare system truly is as families scrambled in desperation for oxygen cylinders and critical care facilities.

Despite these glaring gaps, the government continues to allocate disproportionate funds to promotional advertising rather than strengthening frontline services. Beneath these shortcomings lies a governance ethos steeped in self-praise. In the past decade, over ₹1,500 crores of taxpayers' money has reportedly been funnelled into advertising, even as ongoing issues—such as waste management, air pollution, and traffic congestion—remain woefully neglected. Delhi's air quality is ranked among the worst in the world year after year, yet funds reserved under the National Clean Air Programme (NCAP) are chronically underutilised.

AAP's habit of blaming the Lieutenant Governor or the central government only foments tension rather than cultivating solutions. This relentless tug-of-war with the centre has hamstrung efforts to address urgent concerns in a city of nearly 20 million people. Policy gridlock is more than a bureaucratic snag; it endangers lives when services collapse under pressure. Again and again, Delhi's government has chosen to manufacture and escalate disputes rather than forge the alliances needed to tackle overwhelming challenges—from pollution to unreliable water supply.

Meanwhile, AAP's financial mismanagement puts Delhi's future at risk. Although free electricity and water may appear appealing, these subsidies strain public coffers and divert resources from core sectors like healthcare and education, where needs are most pressing. Ballooning deficits eventually force cutbacks, creating a cycle in which short-term populism supersedes long-term planning. A genuinely people-centric government would strike a prudent balance—offering help to the vulnerable without abandoning foundational reforms.

Now, Delhi braces for another election that promises to be more than a standard democratic exercise. It is an urgent choice between an administration consumed by publicity stunts and one committed to forthright, accountable governance. The city deserves leadership focused on alleviating pollution, upgrading infrastructure, and maintaining high-quality public services rather than orchestrating a perpetual PR campaign. In this context, a "double-engine government"—where the state administration aligns with the centre—appears ever more compelling. In Delhi, such synergy could expedite the rollout of crucial schemes like Ayushman Bharat and the Jal Jeevan Mission, both of which target glaring gaps in healthcare and water availability.

The Bharatiya Janata Party (BJP) presents itself as a viable alternative, backed by a track record of development-led governance and closer ties with the centre. Only such unity can unlock Delhi's full promise and reverse the stagnation of recent years. The shallow announcements must yield to the depth of genuine reform—across water management, transportation, public health, and beyond.

Ultimately, Delhi's trajectory will be determined by its voters' willingness to look past billboards and social media blitzes. If the last decade offers any lesson, it is that grandiose assurances ring hollow without the competence and determination to fulfil them. A new election provides a rare opportunity to reset priorities and demand leadership that treats governance not as a chance for political theatrics but as a genuine mandate to serve.

Delhi deserves a government that works tirelessly to secure clean air, plentiful water, robust schools, and a strong healthcare network. Instead of shiny promises, it needs firm resolve and tangible results. Something that only the BJP can deliver. May Delhi's choice reaffirm its legacy as a beacon of prosperity and progress for all of India. Vote for change. Vote for better governance. Vote for the BJP.

Hype over Substance: A Decade of Disappointment under AAP

Shehzad Poonawalla,
National Spokesperson, BJP and
Utsav Aggarwal, 4th year, SLSN

In 2013, when the Aam Aadmi Party (AAP) stormed onto the political stage in Delhi, it promised revolutionary governance, transparency, and a better quality of life for all. The "opportunist" Arvind Kejriwal stood on the shoulders of Anna Hazare and delivered a curious cocktail of grand promises, lavish ads, and an ever-deepening pothole of unfulfilled dreams for Delhi.

Presently, the narrative is marked differently than the one set a decade ago. While the party built its foundation on the ideals of change, many Delhiites now question the effectiveness of the government they once rallied behind. From swearing on his kids to shaking hands with Congress, from blue WagonR to luxury cars, from promising to live like a common man to building a Rs 52 Crore Sheesh Mahal, from promising to make Yamuna a clean tourist spot by 2020 to contributing most to Yamuna's pollution level, from promising to give European standard roads to delivering a sink-hole model, from

promising a good education model to expelling more than 3 Lakh students in the past two years for fake statistics, from promising drinkable tap water to backing tanker mafia and DJB scams, from promising free electricity to long-lasting power cuts, from promising 24 new hospitals to delivering none, from promising to reduce pollution to 70% under utilisation of NCAP funds to control air quality, from demanding for healthy law and order to coming in favour of criminals like Tahir Hussain and Bibhav Kumar, we all have seen the journey of Aam Aadmi Party in the last 10 years.

Delhi's water management is a textbook example of how lofty promises can drown in poor execution. Residents frequently face a dire water supply crisis, with a daily demand of 1,290 million gallons per day (MGD) and a supply of only 1,000 MGD. A government report reveals that Delhi's water treatment plants (WTPs), designed to process 950 MGD, are overstretched, often handling 990 MGD. There has been a 16.28% surge in water leakage over three years, as per Delhi Jal Board official figures. Despite these grim figures, the Kejriwal government has failed to prioritise robust infrastructure, leaving households struggling for basic necessities.

Meanwhile, the Yamuna River, a lifeline for the city, remains in deplorable condition. Between 2017 and 2021, nearly ₹6,856.91 crore was spent to clean the river, yet its pollution levels have only worsened. The ammonia concentration in the Yamuna—which should not exceed 0.5 parts per million (ppm)—has spiked to over 5.00 ppm in 2024. This spike is attributed to the inefficiency of 22 of Delhi's 36 sewage treatment plants (STPs), failing to meet basic operational standards. Add to this the recurring problem of waterlogging during monsoons, which claimed 18 lives this year alone, and it is clear that the AAP government's handling of water issues is as murky as the Yamuna itself.

A Healthcare Mirage

Healthcare was touted as one of AAP's crown jewels. Yet, beneath the shiny exterior of promises lies a reality marked by delays and inefficiencies. None of the 24 hospitals announced in 2018-19 with a budget of ₹5,590 crore have been completed. Similarly, the much-hyped network of 94 polyclinics fell short, with only 52 operational—and even these are plagued by cost overruns.

The "Mohalla Clinics", hailed as revolutionary, face allegations of mismanagement and expired medicines. Out of the 1,000 promised clinics, Kejriwal and the company have delivered only <55% since 2015. Furthermore, to establish the "supremacy" of its fake scheme, Sanjeevani Yojna, against which the health department of the Delhi government issued a notice calling it "non-existent", the AAP is not implementing the central scheme of Ayushman Bharat. Such a tactic leaves residents wondering whether political optics have overshadowed public welfare.

The Education Model: Numbers over Substance

Education has been another cornerstone of AAP's governance propaganda, but the numbers tell a different story. Government-run schools operate with only 57% of the sanctioned teaching staff, and 84% of principal posts remain vacant. Despite the land being allotted for 13 new schools, none have been constructed in the last eight years. Disturbingly, 2/3rd of schools do not offer science education in classes 11th and 12th. On various occasions, the Aam Aadmi government has been flagged by the Delhi High Court for not maintaining basic standards in the state-run schools.

The party's focus on international acclaim has overshadowed ground realities. Nearly 3 lakh students were expelled between 2022-24, a move critics allege was designed to manipulate pass percentages and bolster the government's narrative. Additionally, the Delhi government has cleverly rerouted students failing twice in classes 9th and 11th to open schooling. Almost 20% of class 9th students drop out every year, with 50% failing in 2019. Many of the remaining ones are transferred to NIOS (National Institute of Open Schooling), leaving a trail of disillusionment behind their 'success stories.' These numbers paint a grim picture for a party that once claimed education as its priority.

Fiscal Mismanagement: The State of the Exchequer

Delhi, traditionally known for fiscal prudence, is now staring at a revenue deficit of approximately ₹1,495.48 crore for the fiscal year 2024-25. The

government's revenue receipts are projected at ₹62,415 crore, while its expenditures soar to ₹63,910 crore. Instead of tightening its belt, the AAP administration has sought a ₹10,000 crore loan from the National Small Savings Fund (NSSF), raising concerns over fiscal responsibility. Delhi's financial health is stressed because of the freebies politics that AAP has adopted in the past 10 years.

The Delhi Jal Board (DJB) exemplifies the mismanagement of public funds. With cumulative losses of ₹73,000 crore and unexplained expenses of ₹28,400 crore, the water body has become a symbol of inefficiency and lack of accountability under AAP's watch.

Corruption Allegations: A Tarnished Image

For a party that came to power on the promise of corruption-free governance, AAP's track record is riddled with scandals. Arvind Kejriwal, often accused of being the "kingpin" in the scrapped 2021-22 excise policy, has faced allegations of demanding ₹100 crore in bribes. Foreign funding violations, a ₹500 crore scam related to non-functional panic buttons, and the misallocation of funds in public works further tarnish the party's image.

Even the flagship Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) has not been spared, with embezzlement claims amounting to ₹250 crore. These scandals, coupled with allegations of bribe money being funnelled into election funds, challenge AAP's moral high ground.

Aam Aadmi Party is not just a pond full of good fish and one crocodile; the whole pond is full of crocodiles. Almost every key member of AAP "Company" has its own list of alleged scams. Arvind Kejriwal – Kingpin of Rs. 100 crores kickbacks from Delhi Excise Policy Scam, Allegations regarding a ₹125 crore project for constructing Sheesh Mahal; Atishi Marlena – Delhi Liquor Scam accused; Manish Sisodia – Arrested in Delhi Liquor Scam, Accused of a scam of Rs 2000 crore in the construction of school rooms by the Delhi government; Sanjay Singh – ED arrest under Liquor Scam; Satendra Jain – money laundering and extortion scam cases going on; Amantullah Khan – famous for misappropriation of funds of Delhi Waqf Board and his hooliganism; Bibhav Kumar for attacking Swati Maliwal and many more.

Conclusion: A Decade of Disappointment

Today, the term "AAP" doesn't stand for Aam Aadmi Party; it stands for "Advertisement Agency Party". The only model that AAP is following is of advertising its hollow promises like Mahila Samman Yojna which are exposed by its own government. Since 2015, AAP has spent more than Rs. 1500 Crores on ads, and Aam Aadmi would have never done that. In comparison, the central government's budget for 'Public Outreach' in 2023-24 was ₹1,090 crore. Shockingly, the Delhi government spent more than 50% of that amount in 2021-22 alone under the guise of "advertisements," leaving taxpayers questioning the priorities of their government.

The social media "influencer" of Indian politics, AAP, has showcased its incompetency throughout these 10 years. Instead of working hard to fulfil their promises, the AAP has found an easy way to play blame-game politics with the LG and the Central Government, leaving the people of Delhi in unliveable conditions.

After a decade in power, the Aam Aadmi Party's governance in Delhi offers more questions than answers. The government's failures are too glaring to ignore whether it's the unclean Yamuna, crumbling healthcare infrastructure, faltering education system, or mounting fiscal irresponsibility. Delhi's residents, who once placed immense faith in AAP, now find themselves grappling with the consequences of a government that promised much but delivered little.

As the city's roads remain waterlogged and its dreams stalled, it's time to ask: When will the Aam Aadmi Party finally rise to its promises, or will its legacy remain one of missed opportunities and broken trust?

Punjab in Crisis: Broken Promises and Governance Failures Under AAP

Amandeep Singh
National Media Incharge,
BJYM

Once known for its prosperity, rich leadership, and economic power, Punjab now stands as a shadow of its former self. The land of Gurus, saints, and heroes has transformed into a state plagued by lawlessness, gangsters, drug mafias, and crippling debts. Over the past few years, the state has witnessed a dramatic decline in almost every sector, from basic living standards and business opportunities to peace, harmony, and brotherhood. Under the rule of the Aam Aadmi Party (AAP), Punjab has seen an alarming rise in crime and a reinvigorated Khalistan narrative, while the promises of progress have remained largely unfulfilled.

AAP came to power in Punjab with an overwhelming majority of 92 out of 117 assembly seats, riding on promises of “BADLAAV” (change). The party vowed to deliver corruption-free governance, improve law and order, and bring revolutionary reforms in education and healthcare. However, three years into their rule, these promises have proven to be nothing more than empty words. The issue of corruption, which AAP had promised to eradicate, was exposed when their Health Minister, Vijay Singla, was caught seeking a 1% commission on government contracts and arrested. Further embarrassing arrests followed, including that of MLA Gajjan Singh

Gajjanmajra, involved in a bank fraud case, and MLA Mohammad Abbas Ansari, arrested for bribery and misuse of power. Such incidents highlight the deep corruption within the party, with even its own representatives engaged in criminal activities. If the legislators themselves are involved in such open corruption, it is fair to question the governance at the grassroots level.

Another disastrous move by the AAP government was the so-called "knowledge-sharing agreement" between Punjab and Delhi, which has drawn widespread criticism. In this unprecedented agreement, official files and senior officers from Punjab are sent to Delhi, where they report directly to the AAP High Command. This undermines Punjab's autonomy and reduces its governance to a mere extension of Delhi's political agenda. Such actions violate the federal structure of India and erode public trust, as the people of Punjab deserve a government that prioritises their interests over party politics.

The state's law and order situation has deteriorated to alarming levels. Reports of gang wars, gunfights, murders, dacoities, snatching, and crimes against women dominate daily news. The murder of singer Sidhu Moosewala in broad daylight and the rise in gang-related violence are just a few examples of how lawlessness has taken root in Punjab. The situation is further exacerbated by notorious gangster Lawrence Bishnoi, who, even while incarcerated in Punjab's jails, openly boasted about his criminal activities in interviews. These interviews, which went viral, serve as a stark reminder of the government's inability to maintain control, not just on the streets but even within its own prison system.

The drug menace In Punjab, once a major concern, remains as rampant as ever. Despite Arvind Kejriwal's promise to eradicate drugs from the state within 60 days of assuming power, this pledge has been nothing more than a hollow promise. The availability of synthetic drugs like "chitta" continues to wreak havoc on the youth, with drugs being sold openly in villages and towns. Despite multiple incidents of heroin and narcotics being seized, the state government has failed to dismantle the drug supply chain, leaving the youth vulnerable to addiction and families devastated by the crisis. The promise of a drug-free Punjab remains unfulfilled, and the government's inability to address this pressing issue has only deepened public disillusionment.

Punjab is also facing an unprecedented financial crisis. The state's debt has soared to an alarming ₹3.47 lakh crore, with the AAP government alone adding ₹50,000 crore in loans since coming to power. The government's focus on populist freebies, like free electricity and water, has drained the state's resources, leaving critical sectors like infrastructure, healthcare, and education underfunded. The absence of a clear economic strategy and reliance on central grants has left Punjab vulnerable. Shockingly, every child born in Punjab today inherits a debt burden of nearly ₹1 lakh, symbolising the dire state of the economy and the government's failure to manage finances responsibly.

The Internal bickering within the AAP in Punjab has further exposed the instability of its leadership. Chief Minister Bhagwant Mann has shown a lack of trust in his own MLAs and ministers, creating a chaotic atmosphere within the government. At the same time, Delhi's leadership appears to have little confidence in Mann, leading to frequent reshuffling of ministers and even replacing political staff in the Chief Minister's Office. This internal conflict has hindered effective governance, eroded public trust, and compromised the ability to make crucial decisions for the betterment of Punjab.

A Wake-Up Call for Punjab's Future

Punjab stands at a crossroads. The promises made by the AAP government have not only been unfulfilled but have also led the state into a period of instability, economic decline, and rising crime. The people of Punjab deserve a government that prioritises their welfare, restores law and order, and ensures a stable and prosperous future for the state. As the cracks within the AAP administration continue to widen, it is clear that Punjab needs urgent leadership and a clear vision for reform if it is to reclaim its place as a prosperous and peaceful state.

The Financial Mismanagement of AAP: A Decade of Economic Decline in Delhi

Vishu Basoya, NEC Member, BJYM

The Aam Aadmi Party (AAP), under the leadership of Arvind Kejriwal, rose to power in Delhi with grand promises of governance reform, fiscal prudence, and transformative policies. However, ten years into their governance, a closer examination reveals an alarming narrative of financial mismanagement, misplaced priorities, and questionable decisions.

A Legacy of Extravagant Spending

One of the most striking aspects of AAP's financial mismanagement is its propensity for exorbitant expenditures on non-essential luxuries. For instance, the renovation of the Chief Minister's official residence cost a staggering ₹52 crore. This included ₹70 lakh for automatic doors and ₹1.15 crore for marble. Such opulence is an affront to the taxpayers and a direct contradiction of AAP's initial promise of simplicity and austerity.

This culture of lavishness is further highlighted by the party's spending on self-promotion. The Delhi government allocated hundreds of crore to publicity campaigns, prioritising image-building over addressing pressing issues like pollution, health, and education.

Infrastructure Development Stagnates

Despite lofty claims, AAP's governance has failed to deliver tangible improvements in critical infrastructure. The Delhi Metro projects have been moving at a slow pace despite the push from the centre due to cooperation and non-seriousness by the AAP government in Delhi. Moreover, the state-run Delhi Transport Corporation (DTC) has not added a single new bus to its fleet in 15 years, exacerbating the public transport crisis.

The situation is equally grim in waste management.

Despite promises to eliminate garbage mountains in Ghazipur and Bhalswa, these towering landfills have only grown, symbolising the failure of AAP's policies. Delhi, once a beacon of modern urban development, now struggles with waste disposal and rampant air pollution, undermining the quality of life for its residents.

Health and Education: Broken Promises

AAP's much-touted "Mohalla Clinics" have been exposed as a hollow facade. While the clinics were advertised as a revolutionary healthcare model, many remain non-functional, poorly equipped, and severely understaffed. The government's failure to operationalise hospital projects despite budgetary allocations further underscores its lack of commitment to healthcare.

Similarly, AAP's education model has fallen short of its ambitious promises. Reports indicate that the infrastructure of government schools remains inadequate, with leaking ceilings and poorly maintained classrooms. Despite increased budgetary allocations, the learning outcomes of students have shown no significant improvement, raising questions about the efficacy of the government's education policies.

AAP's Economic Mismanagement

AAP's fiscal policies have directly contributed to Delhi's economic decline. The party has failed to manage the city's finances responsibly, leading to ballooning debt. This financial recklessness has burdened future generations with the responsibility of repaying loans without any corresponding economic growth or infrastructural development to justify such borrowing.

Additionally, AAP's revenue generation strategies have been marred by inefficiencies and corruption. The excise policy fiasco, where revenue losses ran into hundreds of crores due to irregularities, serves as a glaring example of administrative incompetence.

Environmental Degradation and Public Health Crisis

Under AAP's governance, Delhi has become synonymous with environmental degradation. The air quality in the capital has consistently ranked among the worst globally, with pollution levels crossing hazardous thresholds during winters. AAP's inaction in implementing effective measures to curb vehicular and industrial pollution has left Delhi residents grappling with severe health issues.

The condition of the Yamuna River further illustrates AAP's environmental apathy. Despite repeated promises to rejuvenate the river, untreated sewage and industrial waste continue to pollute it, turning the Yamuna into an open drain rather than a lifeline for the city.

Corruption and Governance Failures

Perhaps the most damning aspect of AAP's governance is the pervasive corruption within its administration. Key leaders of the party have been implicated in scandals, ranging from irregularities in excise policies to misuse of public funds. The charges of favouritism and cronyism have eroded public trust, tarnishing the party's credibility.

Moreover, AAP's inability to maintain a harmonious relationship with government officials has led to administrative paralysis. Frequent confrontations with bureaucrats have hindered the smooth functioning of the government, resulting in delays in project execution and policy implementation.

A Need for Accountability

AAP's decade-long governance in Delhi serves as a cautionary tale of how populist rhetoric, when unaccompanied by responsible governance, can lead to disastrous outcomes. The party's financial mismanagement, combined with its failure to deliver on promises, has left Delhi struggling on multiple fronts—economically, socially, and environmentally.

As Delhiites prepare to choose their leaders in the upcoming elections, it is imperative to demand accountability from AAP for its shortcomings. The need of the hour is a government that prioritises the welfare of its citizens over personal luxuries and political propaganda—a government that can restore Delhi's lost glory and put it back on the path of sustainable development. And only BJP can provide that alternative.

Populysis and Freebruption

Dr. Mrittunjoy Guha Majumdar,
Adjunct Faculty at the National Institute of Advanced Studies Bengaluru
and National Convenor of Mandala, Vijnana Bharati

The Aam Aadmi Party (AAP) emerged as a political force in India, promising clean governance, transparency, and a commitment to addressing grassroots issues. The wave that engulfed Bharat during the India Against Corruption movement under Shri Anna Hazare found a political eddy forming in the national capital. This eddy funnelled into the very power corridors that the movement had so vehemently criticised. This voice was seen by cross-sections of the electorate as a refreshing change. A change from career politicians, dynasts and those running after political clout for the sake of it. A change for those who would address longstanding problems faced by the populace. But what came instead was an age-old tool manoeuvred by politicians for generations: populism. Some scholars regard Akbar's Din-e-Allah as a populist bid to rally support from both Hindus and Muslims, while the Britishers allowed the formation of the Indian National Congress to let largely moderate Indian voices do not much other than writing letters to the British Parliament for some relief from the atrocities of the Raj. In both instances, either fairly quickly (as in the case of Din-e-Allah, which had a little more than a dozen courtiers as followers) or over time (with the growing irrelevance of the

Congress in a Bharat that is decolonising, slowly but surefootedly), the result always has been a failure.
The bubble that the Aam Aadmi Party tried to create also had to burst, and burst it did, in a furious outflux of scandals and irregularities. Kejriwal was implicated in a liquor excise scandal, while many of the top leaders of the party remain in jail. The curious events that have led to where we are today, in states like Delhi and Punjab, have led me to coin two words: 'populysis' and 'freebruption'. 'Populysis' combines `populism' and `paralysis', succinctly capturing the transition from populist rhetoric to policy stagnation, while 'freebruption' merges `freebies' and `disruption', highlighting how excessive giveaways can lead to fiscal instability or fractures. Unfortunately, both these would be characteristics we can associate with the Aam Aadmi Party governments in Delhi and Punjab today. The party's flurry of freebies and populist measures have helped them retain power in states like Delhi and Punjab. But the key question is: at what cost? A deeper analysis reveals significant flaws in its governance model. These shortcomings often stem from an overemphasis on populist measures at the expense of institutional strengthening and sustainable reforms. World over, populist activism has always struggled to translate into effective governance structures. Hugo Chávez's populist regime promised to empower the marginalised and redistribute wealth through social programs. However, his governance led to increased executive power at the expense of democratic institutions. Over time, Chávez's administration suppressed opposition and civil society, ultimately resulting in a political crisis characterised by economic mismanagement and authoritarianism. The Five Star Movement (Movimento 5 Stelle - M5S) in Italy emerged as a populist force promising to disrupt traditional political structures and address citizens' grievances. While it gained significant electoral success, M5S struggled with internal cohesion and governance once in power. The party's lack of experience in managing complex governmental processes led to policy inconsistencies and difficulties in coalition-building, ultimately undermining its initial appeal and effectiveness. The list goes on and on, and in there, we can now safely add the Aam Aadmi Party.

In Delhi, AAP's governance has been characterized by a focus on welfare measures and populist policies, such as free electricity, water subsidies, and flagship programs like Mohalla Clinics and model schools. While these initiatives have garnered public support and international attention, they often mask deeper systemic issues that remain unresolved. One of AAP's defining features is its emphasis on providing free services to citizens.

For instance, The Delhi government allocated ₹3,250 crore for power subsidies in the 2023-24 budget, with an additional ₹100 crore added later, bringing the total to ₹3,350 crore. This reflects a significant increase in the subsidy budget over the years, which has risen from ₹2,405.6 crore in 2019-20 to nearly ₹3,350 crore in the current fiscal year. While many consumers benefit from these subsidies—especially those using up to 200 units of electricity per month, who pay no bill—those consuming more than this threshold face higher tariffs. The PPAC is a surcharge that helps cover fluctuations in power purchase costs for distribution companies (discoms). Recent increases in coal and fuel prices have necessitated higher PPAC rates, which can range from 6.75% to 8.75%, ultimately impacting non-subsidized consumers more heavily. The Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) has maintained a uniform tariff structure, but adjustments such as the Power Purchase Adjustment Cost (PPAC) have led to increased costs for consumers who do not qualify for subsidies.

Similarly, the party's free water policy allows residents to use up to 20,000 litres per month at no cost. However, this policy has resulted in significant revenue losses for the Delhi Jal Board (DJB), which reportedly faced a debt burden exceeding ₹15,000 crore as of 2023. While these subsidies provide immediate relief, they divert essential resources from critical infrastructure development, such as modernising sewage systems or improving water quality. The long-term economic sustainability of these measures remains questionable.

The Mohalla Clinics program has been celebrated as a revolutionary step in accessible healthcare; however, ground reports highlight significant

challenges. Many clinics face shortages of essential medicines, staff, and diagnostic facilities. For instance, patients with conditions like haemophilia have struggled to obtain life-saving injections, leading to distress and confrontations at healthcare facilities due to the unavailability of critical drugs. Patients often leave clinics without necessary medications, receiving only prescriptions or notes instructing them to purchase drugs from private pharmacies, which many cannot afford. Many clinics operate with a shortage of doctors and support staff. Reports indicate that several medical officer positions remain unfilled, leading to overwhelming patient loads—some clinics see up to 150 patients daily with inadequate staffing.

Clinics frequently lack basic diagnostic facilities, forcing patients needing tests (like MRIs or ultrasounds) to seek care at larger hospitals, which can be inconvenient and time-consuming. Essential items for treatment, such as plaster for fractures or even basic medical supplies, are often unavailable, further complicating patient care. The list of 109 free medicines provided at Mohalla Clinics does not cover all necessary ailments. The list of essential drugs is also restrictive for doctors because sometimes they cannot prescribe better-suited salts or medicines not on the list. Critics have argued that these clinics prioritise visibility over substantive healthcare reform as Delhi’s larger public healthcare system continues to grapple with inadequate funding and overcrowded hospitals. Medical data is also not properly maintained. In 2020, Praja, a nonprofit organisation, submitted an RTI request to identify the ten most reported diseases at Mohalla Clinics. Still, by February 6 of that year, only three of Delhi's eleven districts had responded. The report emphasised that effective disease surveillance requires standardised patient record-keeping across all clinics, as discrepancies in data reporting were noted among the districts.

Despite some improvements in Delhi's education sector, significant challenges persist that severely undermine the quality of education. A critical shortage of qualified teachers is one of the most pressing issues, with the Delhi government currently facing a deficit of approximately 1,000 Post Graduate Teacher (PGT) positions, as only 283 PGTs are available to serve over 9,500 students with disabilities across 609 government schools at the senior secondary level. The consequences are dire: in the 2023-24 academic year alone, over 100,000 ninth-grade students in Delhi failed their annual exams, alongside more than 46,000 students in Class 8 and 50,000 in Class 11. Furthermore, the overall enrolment in Delhi government schools has decreased by over 30,000 students compared to the previous year, attributed largely to perceptions of poor educational quality and inadequate facilities. These systemic issues—coupled with high student-to-teacher ratios that often exceed 47:1—hinder personalised instruction and contribute to a cycle of underachievement and disengagement among students. Addressing these challenges is essential for restoring confidence in the public education system and ensuring equitable access to quality education for all students.

In Punjab, AAP's victory in 2022 was seen as a significant milestone for the party; however, governing this state presents a more intricate challenge compared to Delhi. Punjab's fiscal crisis, entrenched agricultural issues, and complex socio-political dynamics have revealed the limitations of AAP's governance model. Punjab is facing a serious financial crisis, with its debt-to-GDP ratio projected to exceed 50% in the near future. As of 2024, the state's debt is estimated to reach approximately ₹3.74 lakh crore, which constitutes more than 46% of its Gross State Domestic Product (GSDP) of over ₹8 lakh crore. This figure places Punjab among the most indebted states in India, with reports indicating that its debt-to-GSDP ratio is among the highest in the country. The financial situation has been exacerbated by various factors, including substantial government subsidies and a heavy reliance on borrowing to manage existing debts.

For instance, Punjab's government has significantly increased its debt burden since the Aam Aadmi Party (AAP) took power, with allegations that the debt rose by ₹50,000 crore within 18 months of their administration. Additionally, the Reserve Bank of India (RBI) has highlighted Punjab's precarious fiscal health, noting that it ranks among the top five most indebted states nationally and has one of the

highest per capita debts. The state's ongoing financial challenges have led to calls for a bailout from the central government, although experts question the feasibility of such assistance given the high levels of debt already present. The state's financial health is among the worst in India, with a debt-to-GDP ratio exceeding 50% as of 2024.

The Aam Aadmi Party (AAP) has faced significant criticism during its tenure in Punjab, particularly concerning its welfare schemes and governance challenges. The introduction of the free electricity scheme, which offers up to 300 units per month at no cost, has led to a dramatic increase in domestic connections, with nearly 90% of households receiving zero electricity bills. While this initiative has garnered popularity, it has also resulted in substantial financial strain on the state's resources, with projected subsidy costs expected to reach ₹21,909 crore by 2024-25. This figure includes ₹10,175 crore allocated for agriculture, raising concerns about the sustainability of such populist measures amid Punjab's already precarious fiscal situation. The reliance on these welfare schemes has contributed to a growing revenue deficit, projected at ₹24,000 crore for the upcoming fiscal year.

AAP's focus on freebies detracts from essential reforms needed in the agricultural sector, which is facing a severe crisis. The state's farmers continue to struggle with high debt levels, with institutional debt reaching ₹73,673 crore by 2023. Despite promises of support, reports indicate that 14 farmers committed suicide within just 50 days of AAP taking office, highlighting the ongoing agrarian distress that the government has failed to adequately address. Additionally, law and order issues have escalated under AAP's governance. Rising drug trafficking cases and communal tensions have raised alarms about the effectiveness of the administration in maintaining peace and security. Regional complexities have also posed challenges for AAP, particularly regarding water-sharing disputes with Haryana.

A common thread between AAP's governance in both states is its reliance on populist measures rather than institutional reform. While welfare schemes yield short-term political gains, they often fail to address the root causes of systemic issues. For instance, despite promises of transformation in urban infrastructure in Delhi, persistent problems such as poor waste management and air pollution remain unaddressed due to inadequate investment in sustainable urban planning. The disconnect between activism and governance is another critical aspect of AAP's challenges. The party's activist roots emphasised immediate action and public mobilisation; however, this focus has not effectively translated into governance. The preference for high-visibility projects often undermines robust governance frameworks.

Despite professing a commitment to decentralisation, AAP has done little to empower local governance structures such as municipal bodies in Delhi or panchayats in Punjab. In fact, centralisation of power has been a hallmark of AAP's governance model in Delhi. Chief Minister Arvind Kejriwal's office wields significant control over decision-making processes, often sidelining bureaucratic procedures and expert opinions. This became farcical when Atishi kept the CM's chair vacant after taking oath as Chief Minister of Delhi, in what seemed like a perversion of the selflessness of Bharat in forsaking the throne and yet administering Ayodhya in Shri Ram's absence during his exile. This centralisation has led to inefficiencies and delays in governance. The ongoing conflicts between the Delhi government and the Lieutenant Governor further underscore the challenges associated with this centralised approach. Also, the Ayushmaan Bharat is not applicable in Delhi. The only other state that has not implemented this important national scheme is West Bengal. It is clear that Delhi has no hope of progress and development under the AAP. The party lacks any vision for the future or to tackle the numerous challenges facing the megapolis of Delhi.

Toxic Legacy: Environmental Degradation under AAP

Sushant Mehlawat SEC Member, BJYM Delhi

The Aam Aadmi Party (AAP), which once rose to power promising a cleaner, greener, and healthier Delhi, has left the city grappling with some of the worst environmental and water crises in its history. From escalating air and river pollution to acute water supply issues, AAP's governance has been characterised by empty promises and ineffective action plans. These failures have not only tarnished the party's claims of delivering transformative governance but have also significantly impacted the lives of Delhi's residents.

Air Pollution: A Toxic Legacy

Under AAP's leadership, Delhi has consistently been ranked as one of the world's most polluted cities. According to reports, the city witnessed over 12,000 deaths in 2024 due to air pollution-related illnesses, highlighting the severe health crisis inflicted by poor air quality. Despite numerous promises, the government has failed to implement robust policies to tackle vehicular emissions, industrial pollution, and crop-burning-related smog. AAP ruled Punjab has not taken any concrete action to curb stubble burning during winter, which is the major contributor to Delhi's winter smog.

One of the glaring examples of mismanagement is the lack of proactive measures during winter months when air quality dips to hazardous levels. The much-publicized "Odd-Even" scheme for vehicular traffic proved to be a temporary band-aid rather than a long-term solution. Moreover, the government's reliance on publicity stunts instead of actionable reforms has left the citizens of Delhi choking on toxic air.

The Yamuna: A River Turned Drain

The Yamuna River, once considered Delhi's lifeline, has been reduced to a stinking drain under AAP's governance. Despite grand announcements of rejuvenating the river, the government has done little to address the untreated sewage and industrial effluents that continue to flow unabated into the Yamuna. The installation of sewage treatment plants (STPs) remains inadequate, and

existing plants are operating below capacity due to poor maintenance.

AAP's failure to enforce regulations on industries polluting the river has further exacerbated the crisis. For instance, in the past decade, the river has seen an alarming increase in the levels of ammonia and heavy metals, making the water unfit for consumption or even basic human contact. This degradation has not only impacted aquatic life but has also affected thousands of farmers and residents who depend on the river for their livelihoods.

Water Supply Crisis: Broken Promises

AAP's promise of providing free and clean water to every household has turned into a nightmare for Delhi's residents. The city's water supply, managed by the Delhi Jal Board (DJB), is plagued with inefficiencies and corruption. A significant portion of the city still relies on tanker mafias for their daily water needs, as the government has failed to ensure equitable and consistent water distribution. In many parts of Delhi, the water supplied is not only scarce but also contaminated. Tests have revealed that Delhi's water quality is among the worst in the country, with the presence of harmful bacteria and pollutants exceeding safe limits. The government's inability to upgrade infrastructure and address leakages in the water distribution system has compounded the crisis.

Environmental Degradation: A Systemic Failure

Delhi's environmental woes extend beyond air and water pollution. The city's waste management system is in shambles, with massive garbage mountains in Ghazipur, Bhalswa, and Okhla continuing to grow unabated. These sites, emitting toxic gases, are a constant health hazard for nearby residents. Despite promises to clear these landfills, AAP has failed to take any meaningful action.

The lack of green cover and unchecked urbanisation have further deteriorated Delhi's environment. AAP's failure to implement sustainable urban planning has led to shrinking forests, vanishing biodiversity, and increased urban heat islands, making Delhi's climate more inhospitable with each passing year.

Misplaced Priorities and Ineffective Governance

AAP's environmental failures stem from a combination of misplaced priorities and ineffective governance. The party has focused more on self-promotion and publicity campaigns rather than investing in long-term solutions. For instance, while crores have been spent on advertising the government's achievements, key projects like wastewater treatment plants and air quality monitoring systems have seen minimal progress.

Moreover, AAP's confrontational approach with central agencies and bureaucratic inefficiencies have delayed critical environmental initiatives. The lack of collaboration and accountability has left Delhi's residents paying the price for governmental apathy.

The Way Forward

To address Delhi's environmental and water crises, it is imperative to adopt a multi-pronged strategy. The government must prioritise investments in clean energy, modernise waste management systems, and enforce stricter regulations on industries and vehicles contributing to pollution. Revamping the Delhi Jal Board and ensuring equitable water distribution should also be key priorities.

Moreover, a holistic approach to urban planning that includes increasing green cover, conserving water bodies, and mitigating climate risks is essential for sustainable development. Transparency, accountability, and public participation in decision-making processes can help rebuild trust and ensure the effective implementation of policies.

Delhi's worsening air and river pollution, coupled with its water supply crisis, is a direct result of AAP's governance failures. The party's inability to deliver on its promises has left Delhi's environment in shambles, affecting the health, livelihoods, and quality of life of millions of its residents.

However, the track record of AAP shows that it is simply not concerned nor capable of responding to these challenges. Only a BJP government in Delhi can provide working solutions to environmental issues and a vision for the development of Delhi.

भ्रष्टाचार, अपराध और वादाखिलाफी: आम आदमी पार्टी के शासन का सच

डॉ. वृंदा काल्हेर
प्रदेश प्रमुख, पॉलिसी एंड रिसर्च
भाजपा युवा मोर्चा, हरियाणा

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में पूरा देश कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त था। केन्द्र और दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ कांग्रेस के राज में 2G, कामनवेल्थ, और कोयला घोटाले जैसे अरबों खरबों के घोटाले हुए। उसी दौरान सन् 2011 में देश के एक जाने माने समाजसेवी अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और धीरे धीरे यह देशव्यापी हो गया। आंदोलन तो था कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकिन असल में यह अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों के लिए राजनैतिक लॉनचपैड साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों की राजनैतिक महत्वकांक्षा के गर्भ से नवंबर 2012 में एक नई पार्टी निकली जो थी आम आदमी पार्टी। आंदोलन के मंच से दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों की फाइलें लहराते केजरीवाल ने अब तक के राजनीतिक सफर में क्या किया आईए इसका लेखा जोखा करते हैं।

दिल्ली और पंजाब में सरकारः

सन् 2013 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। कांग्रेस के खिलाफ गुस्से का भरपूर फायदा केजरीवाल एंड कंपनी को मिला। आम आदमी पार्टी 28 सीट लेकर राज्य में दूसरे नंबर पर रही। आंदोलन के समय पानी पी - पी कर कांग्रेस को कोसने वाले केजरीवाल ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर उसी कांग्रेस पार्टी से मिलकर सरकार बनायी, जो महज़ 49 दिन चली। लेकिन अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को अविश्वसनीय जनसमर्थन मिला। पार्टी 70 में से 67 विधानसभा सीटें जीती तथा तब से दिल्ली प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। इसके बाद 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली। दिल्ली की भांति ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को अविश्वसनीय बहुमत मिला और पार्टी 117 में से 92 विधानसभा सीटें जीत कर पंजाब की सत्ता पर काबिज़ हुई।

भ्रष्टाचार और अपराधों का अड्डा बनी आपः

राजनीति को स्वच्छ करने को आम आदमी पार्टी ने जो झाड़ू चलाया, उस झाड़ू ने ऐसा गंद डाला है कि जनता त्राहि त्राहि कर उठी है। यह सच ही है कि ' जो दावे करते थे रहनुमा होने के, उन्होंने ही लूटा बेरहम होकर के '। सन् 2020 में छपी एक रिर्पोट के अनुसार दिल्ली में पिछले विधान सभा चुनावों में आमआदमी पार्टी के 70 में से 36 विधानसभा चुनाव प्रत्यक्षियों पर गंभीर अपराधिक मामले चल रहे थे। और कुछ ऐसा ही हाल पंजाब विधान सभा चुनावों में भी था। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के जीते हुए विधायकों में से आधे लोगों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं। यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी के कई बड़े-बड़े नेता या तो जेलों में बंद हैं या ज़मानत पर हैं। यहां तक कि भृष्टाचार के आरोपों के कारण शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल तक जाना पड़ा। इनके इलाका सत्येन्द्र जैन, अमानतुल्लाह खाना , सोमनाथ भारती, विजय सिंगला, ताहिर हुसैन, संजय सिंह, संदीप कुमार, नरेश यादव, प्रकाश जरवाल, अखिलेशपति त्रिपाठी, मनोज कुमार, , शरद चौहान, जीतेन्द्र सिंह तोमर जैसे नेता गंभीर आपराधिक मामले झेल रहे हैं।

आंकड़े चीख रहे हैं कि जनता से धोखा हुआ :

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक बेंच ने दिल्ली की प्रदेश सरकार को लताड़ लगाते हुए नवंबर 2024 में कहा कि आपकी सरकार सिर्फ मुफ्त की रेवडियां बांट रही है, जबकि प्रदेश की तरक्की व इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं हैं। और यह सत्य ही है कि आप सरकार विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई हैं। दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी यही हाल है। जिस तरह के चुनावी वायदे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किए, धीरे - धीरे सब ध्वस्त हो गए। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा मारी गई बड़ी-बड़ी ढींगें आजकल सोशल मीडिया पर चुटकुलों की तरह बज रही हैं और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति जिलेंस्की से की जा रही है। और दोनों राज्यों के आंकडे इनकी हकीकत ब्यान कर रहे हैं :

• **शिक्षा**: आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया, बड़े-बड़े दावे किए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दिल्ली के शिक्षा मॉडल का महिमामंडन किया गया। लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते।

दिल्ली में:

पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। नीतिआयोग (2022) के अनुसार, दिल्ली में 8वीं कक्षा के 74% बच्चे गणित में बुनियादी दक्षता हासिल करने में विफल रहे। यहां तक कि वर्ष 2023-24 में नवीं कक्षा के 36% विद्यार्थी फेल हो गए। जस्टिस संजय कौल की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पाया कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक केजरीवाल सरकार ने 1100 करोड़. रुपए मीडिया और प्रचार पर खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही प्रचार बजट में कटौती की गई। लेकिन झूठ कितना भी बोला जाए बकरी गाय नहीं बन सकती।

पंजाब में:

भगवंत मान ने भी केजरीवाल की तर्ज पर बड़े-बड़े दावे किए। पुराने स्कूलों को नया पेंट करके 'स्कूल ऑफ एमीनैंस' नाम दिया। लेकिन हकीकत यह रही कि वर्ष 2023 में सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा के छात्रों का ड्रॉपआउट रेट 20.6% तक पहुंच गया, जोकि उत्तरी भारत में अब तक का सर्वाधिक हैं। 10वीं के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत भी लगातार गिर रहा है। ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे

पेयजल और शौचालय की कमी अभी भी बनी हुई है। पंजाब में एक कहावत है, 'गल्लां दा कड़ाह '। बस पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने वही बनाया है।

• स्वास्थ्य: मोहल्ला क्लीनिक का असफल मॉडल

आम आदमी पार्टी ने "मोहल्ला क्लीनिक" को अपनी स्वास्थ्य नीति का केंद्र बिंदु बनाया। हालांकि, यह मॉडल ज़मीनी स्तर पर नाकाफी साबित हुआ।

दिल्ली में:

वर्ष 2023 में, कुल 1000 घोषित मोहल्ला क्लीनिकों में से केवल 550 कार्यरत हैं। दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में 30% डॉक्टर और 40% नर्सिंग स्टाफ की कमी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार, दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2022 तक मात्र 10 थी, जो आवश्यक संख्या से बहुत कम है।

पंजाब में:

ग्रामीण क्षेत्रों में 60% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के कार्यरत हैं। पंजाब में भी पुराने अस्पतालों को नया रंग करके मोहल्ला क्लीनिक का नाम दिया गया। महज़ रंग़ रोगन और नाम बदलने पर ही लाखों खर्च कर सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया गया। नशा छुड़वाने के इलाज केंद्रों की संख्या जरूरत से बहुत कम है।

• कृषि: पंजाब के किसानों के साथ धोखा

आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन के वक्त किसानों से बड़े-बड़े

वायदे किए थे। और कहा था कि पंजाब में सरकार बनने के बाद किसानों के सारे मसले चुटकियों में हल कर दिए जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद मज़बूरियों के रोने रो-रो कर और बहानेबाजी से किसानों को ठेंगा दिखा दिया।

पराली जलाने का मुद्दा:
पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए कोई प्रभावी समाधान नहीं दिया, यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार ने भी आरोप लगाया कि लाहौर में वायु प्रदूषण का कारण पंजाब की पराली से निकलने वाला धुआं है।

• भ्रष्टाचार: पारदर्शिता का अंत
आम आदमी पार्टी का "भ्रष्टाचार मुक्त शासन" का दावा उनके शासनकाल में खोखला साबित हुआ। बल्कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बता दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में हम आपसे बेहतर कर सकते हैं।

दिल्ली शराब घोटाला:
वर्ष 2022-23 में शराब नीति में कथित अनियमितताओं के कारण सरकार को करीब ₹2873 करोड़ का नुकसान हुआ। और इसी शराब घोटाले के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा।

पंजाब में रेत माफिया:
वर्ष 2023 में, पंजाब में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया कि अवैध खनन से सरकार को ₹400 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की।

सरकारी ठेके और नियुक्तियां:
ठेके देने में भाई-भतीजावाद और रिश्वतखोरी के कई गंभीर आरोप लगे। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी कार्यवाही चुनिंदा ही हुई, ज्यादातर शिकायतें कचरा पेटी में ही समा गईं।

• कानून-व्यवस्था: विफलता और अराजकता
आम आदमी पार्टी के शासन में कानून-व्यवस्था दोनों राज्यों में बुरी तरह चरमरा गई।

दिल्ली में:
वर्ष 2023 में, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 40% की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, हर दिन औसतन 3 बलात्कार और 5 हत्याएं होती हैं।

पंजाब में:
जब से भगवंत मान की सरकार सत्ता में आई है तब से गैंगस्टरों को तो जैसे खुली छूट मिल गई है। सिद्धू मूसेवाला और कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों की दिनदिहाड़े हत्याएं हुईं। गैंगेस्टर शरेआम फिरौती मांगते हुए सोशल मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखे गए। नशे के व्यापार के कारण पंजाब में अपराध दर 25% तक बढ़ी है।

• शहरी और ग्रामीण विकास: असंतुलन और लापरवाही
आम आदमी पार्टी का ध्यान मुख्य रूप से शहरी मतदाताओं को लुभाने पर केंद्रित रहा, जिससे ग्रामीण और शहरी विकास दोनों प्रभावित हुए।

दिल्ली में:
वर्ष 2023 में, सीवेज और कचरा प्रबंधन पर 50% परियोजनाएं अधूरी रहीं। वर्ष 2017 से अब तक दिल्ली सरकार
यमुना नदी की सफाई के लिए ₹7000 करोड़ खर्च चुकी है, लेकिन नदी की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई हैं।

पंजाब में:
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

• बिजली और पानी: अव्यवस्थित प्रबंधन
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली और पानी का वादा किया, लेकिन इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ी। लंबे-लंबे बिजली कटों से जनता परेशान है।

दिल्ली में:
2023 में बिजली सब्सिडी का बजट ₹3600 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे अन्य बुनियादी सेवाओं के बजट में कटौती करनी पड़ी।
अनियमित जल आपूर्ति और बढ़ते जल संकट ने जनता को परेशान किया। टैंकर माफिया से मुक्ति के दावे खोखले साबित हुए हैं। टैंकर माफिया से दिल्ली की जनता जूझ रही है।

पंजाब में:
जब से भगवंत मान की सरकार ने जनता को 600 यूनिट फ्री बिजली का लॉलीपाप दिया है, तब से पंजाब में बिजली कटौती का औसत 8 घंटे प्रति दिन रहा। इसी वजह से पंजाब की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हिमाचल और हरियाणा में शिफ्ट हो गई हैं। कृषि को भी बिजली आपूर्ति न होने के कारण काफी नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनी रही।

आम आदमी पार्टी का शासन मॉडल केवल विज्ञापनों और प्रचार तक ही सीमित रहा। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली और पंजाब में उनकी नीतियां जनता की समस्याओं को हल करने में विफल रही हैं। लेकिन करोड़ों के विज्ञापन, प्रचार के विभिन्न साधन भी झूठ को कितनी देर ढंक सकते हैं। जनता ने केजरीवाल का शीश महल भी देखा हैं और शराब घोटाला भी। जनता ने देखा है भ्रष्टाचार और अपराधों में लिप्त आम आदमी पार्टी के नेताओं को। चुनाव दर चुनाव कैसे झूठ को परोसा गया। पंजाब की महिलाएं आज भी 1000 -1000 रुपया मांग रही हैं , जिसकी गारंटी केजरीवाल ने दी थी। और ऐसी कई घोषणाएं अब तक धरातल पर अंकुरित न हो पाई हैं। हां ठीक है कि अब तक झूठ बड़े करीने से बेचा गया है। लेकिन जनता सब देख रही है और वो समय पर जवाब भी देगी।

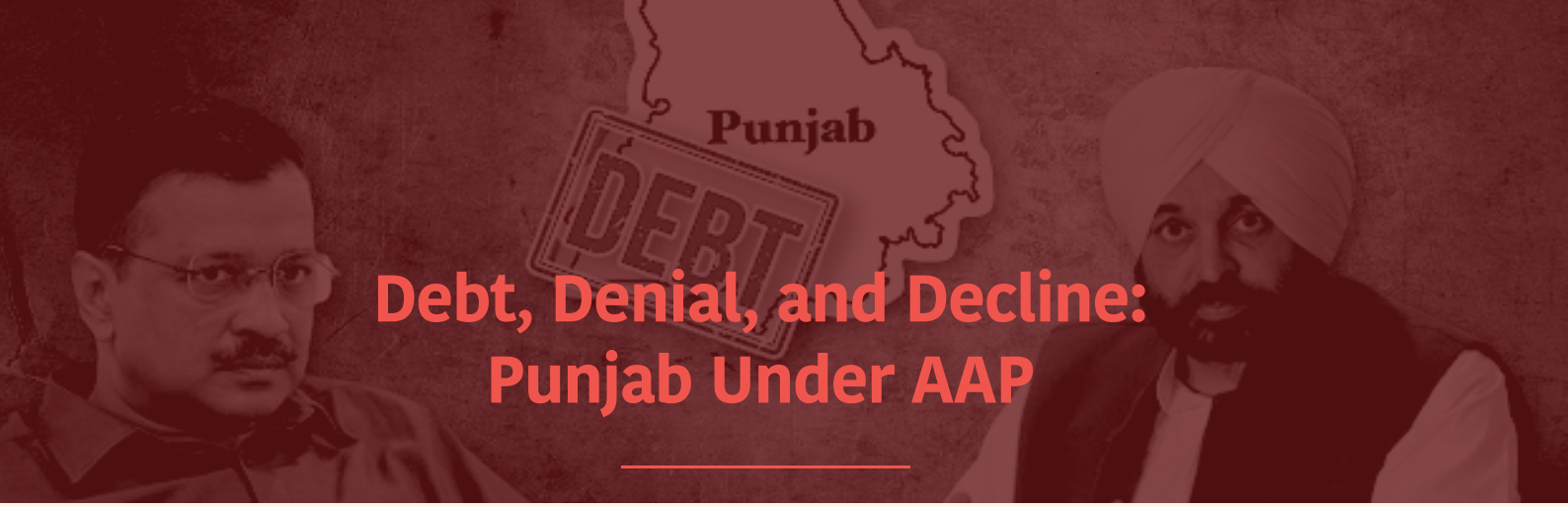

Debt, Denial, and Decline: Punjab Under AAP

Lakshit Mittal
Student body President at the Indian School of Business and
member BJYM National Policy Research and Training

Punjab, a state that once symbolised the prosperity of India's Green Revolution, now faces a severe economic crisis. Under the misrule of the Aam Aadmi Party (AAP), helmed by Chief Minister Bhagwant Mann and backed by Arvind Kejriwal's central authority, the state has descended into financial chaos. AAP's policies in Punjab reveal a dangerous trend of prioritising populist politics over sustainable development, leaving the state saddled with mounting debt and dwindling economic prospects.

The Alarming Debt Spiral

The numbers tell a grim story. Punjab's debt has ballooned to a staggering ₹3.51 lakh crore, as per the 2024 budget estimates, and is expected to rise to ₹3.74 lakh crore by the end of the 2024-25 fiscal year. This figure represents more than 46% of the state's Gross Domestic Product (GDP), projected at over ₹8 lakh crore. For every resident of Punjab, this translates to a personal debt burden of ₹1.24 lakh—a stark reminder of the state's deteriorating fiscal health.

The AAP government, however, has chosen to ignore these alarming signs. Instead of adopting fiscal prudence, it continues to borrow heavily, effectively mortgaging Punjab's future to fund its populist policies. Since AAP took power in March 2022, the state's debt has increased by ₹50,000 crore. This is not just mismanagement; it is a betrayal of the people of Punjab.

Borrowing for Votes, Not Growth

AAP's governance model is rooted in populist giveaways aimed more at securing electoral victories than addressing the long-term needs of the state. The state budget reveals a troubling allocation of resources: ₹9,330 crore for power subsidies for agriculture and ₹7,780 crore to provide "zero bills" for domestic consumers using less than 300 units of electricity per month. While these schemes may resonate with voters, they come at a massive cost to Punjab's fiscal health.

In contrast, capital expenditure—a key driver for growth and development—has been slashed by ₹3,000 crore compared to the previous year. The government plans to spend only ₹7,400 crore on capital projects this year, a stark decline from the ₹10,300 crore allocated last year. It can also be seen in contrast to the Rs. 16,300 crore capital outlay of the Haryana government in 2024-25. This myopic approach underscores AAP's focus on short-term political gains rather than investing in infrastructure, industrialisation, or public services that could drive long-term prosperity.

A State in Decline

Punjab's economic trajectory paints a worrying picture. Once an economic powerhouse with a robust GDP share during the Green Revolution, the state's contribution to India's GDP has plummeted to 2.4% in 2023-24, down from 4.3% in 1990-91. This decline is not accidental. Punjab's over-dependence on agriculture and a lack of diversification into industrial or service sectors has created a form of 'Dutch disease,' stifling the state's economic growth.

Despite these challenges, the AAP government has shown little inclination to address the structural issues plaguing Punjab. The revenue deficit for the first half of the 2024-25 fiscal year stands at 79% of the total projected deficit of ₹23,198 crore. Revenue receipts amount to ₹41,709 crore, while revenue expenditure has already reached ₹60,011 crore—an unsustainable gap that highlights the government's inability to manage resources effectively.

The Cost of Freebies

The obsession with freebies has further exacerbated Punjab's fiscal woes. Beyond power subsidies, a significant chunk of the budget is spent on non-productive expenditures. For instance, over ₹35,000 crore is allocated for salaries and wages, ₹20,000 crore for pensions, and ₹24,000 crore for interest payments. These figures leave little room for investment in development projects that could revive the state's economy.

AAP's model of governance, heavily reliant on freebies, not only drains the state's coffers but also discourages productive economic activity. Subsidies and handouts, while politically expedient, do little to create jobs, attract investments, or improve living standards in the long term.

Denial and Deflection

The AAP government's response to Punjab's financial crisis has been one of denial and deflection. Instead of acknowledging the severity of the situation, the leadership has indulged in political theatrics, blaming previous administrations and seeking massive funds from the central government. In a meeting with the Finance Commission in July, Chief Minister Bhagwant Mann requested ₹1.32 lakh crore for development, agriculture, and tackling drug abuse. However, this plea rings hollow when viewed against the backdrop of the government's reckless fiscal policies.

Three committees led by eminent experts, such as Arvind Subramanian, Montek Singh Ahluwalia, and Arbind Modi, have provided recommendations to address Punjab's economic challenges. Yet, the AAP government has largely ignored their findings, choosing instead to focus on political populism.

The Politics of Populism

AAP's strategy in Punjab is emblematic of its larger political ethos—prioritising electoral gains over governance. By focusing on populist measures, the party has not only compromised Punjab's economic stability but also undermined the principles of fiscal responsibility. Every free power unit, every waived bill, and every unnecessary subsidy is paid for not by the government but by the taxpayers and future generations of Punjabis.

The contrast between Punjab and Haryana is instructive. Once part of the same state, their economic trajectories have diverged sharply. While Haryana has diversified its economy, attracting investments in industries and services, Punjab remains trapped in an agrarian economy with declining returns. This divergence underscores the failure of the AAP government to capitalise on Punjab's potential.

A Call for Accountability

Punjab stands at a crossroads. Its burgeoning debt, declining economic output, and fiscal mismanagement under AAP threaten to derail the state's future. The need of the hour is a leadership that prioritises sustainable development over political gimmicks. Investments in infrastructure, education, healthcare, and industrialisation must take precedence over subsidies and handouts.

AAP's governance in Punjab is a cautionary tale of how populism can devastate a state's economy. The people of Punjab demand accountability and transparency from their leaders. The state's legacy as a cultural and economic powerhouse cannot erode further.

AAP's policies may win votes in the short term, but their long-term consequences are dire. By borrowing against the future to fund today's electoral prospects, the party is not just mismanaging Punjab's finances—it is mortgaging the dreams and aspirations of its people.

झूठे वादों की राजनीतिः केजरीवाल का मॉडल बेनकाब

चन्दन कुमार
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार भाजपा शासित प्रदेश के योजनाओ का नकल करने की कोशिश मे लगी हुई है! अरविन्द केजरिवाल मध्य प्रदेश मे भाजपा की लाड़ली बहना योजना को प्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली मे लागू करना चाहते है! जिससे उन्होंने दिल्ली विधानसभा मे यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया की दिल्ली के महिलाओ को प्रति माह एक हजार रुपया उनके खाते मे डाले जायेंगे! विधानसभा सत्र के बाद वो अपने सभाओ के माध्यम से यह राशि बढ़ाकर इक्कीस सौ रुपया देने की बाते कर रहे है! जबकि दिल्ली में अभी तक किसी भी महिला के खाते में कोई पैसा नहीं आया है, यह केवल अभी घोषणा मात्र है! इसके इतर भाजपा ने जिस राज्य मे यह घोषणा की थी वहाँ पर चुनाव से पहले ही महिलाओ के खाते मे पैसे डालने शुरू कर दिए थे और अभी भी जारी है! जैसे की मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि! अब सवाल यह उठ रहा है कि केजरिवाल के घोषणा पर दिल्ली की जनता भरोसा कैसे करें? क्योंकि खुद केजीवाल जनता से अपने दस साल के शासन काल मे कई वादा खिलाफी कर चुके है! उन्होंने खुद ही इससे स्वीकार भी कर लिया है!

अपने एक साक्षात्कार के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविन्द केजरिवाल ने यह स्वीकार किया है कि, वे तीन मुख्य मुद्दों पर काम नहीं कर पाय है ! जिसमे उन्होंने पहला मुद्दा यमुना की सफाई का बताया ! जो कि उनके सरकार के पिछले घोषणा पत्र मे शामिल था ! जबकि केंद्र सरकार के तरफ से हजारों करोड़ रुपये यमूना सफाई के नाम पर आवंटित भी किया जा चुका है ! उसके बाद उन्होंने दूसरा मुद्दा दिल्ली मे पानी की सप्लाई का बताया कि इसपर भी वो काम नहीं कर पाय है ! जबकि दिल्ली मे ज्यादातर लोग पानी के कारण कैंसर जैसे भयानक बीमारी से जूझ रहें है ! इक्कीस हजार लोग दिल्ली के अस्पतालों मे पानी पीने के कारण मर चुके है ! अब सवाल यह है कि उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली वालों के नल मे नाली के पानी आ रहे है ! तीसरा मुद्दा उन्होंने बताया है कि दिल्ली की सड़के उनके हिसाब से नहीं बन पाई !

अब अरविन्द केजरिवाल के ही बातों को माने जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किये है तो, यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जिन्होंने अपना खुद का वादा नहीं पूरा किया जिसका उनको खेद भी है! वे अब जो वादे कर रहे है उसपर कैसे भरोसा किया जा सकता है ?

इसके आलवे वे दिल्ली मे केंद्र सरकार के कई योजनाओ को लागू ही नहीं होने दिया जिसका फायदा दिल्ली की जनता को मिले ! दिल्ली मे पिछले दस सालों मे एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनने दिया गया ! दिल्ली की जनता को आयुष्मान कार्ड जैसे योजना से वंचित रखा गया ! प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली मे नहीं लागू होने दिया गया ! यदि दिल्ली के किसी भी गरीब व्यक्ति को केंद्र सरकार के इन योजनाओ से लाभ मिलता तो इसमे क्या दिक्कत थी ! जो इन गरीब कल्याणकारी योजनाओ से दिल्ली की जनता को केजरिवाल ने वंचित रखा ?

लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव मे भाजपा का प्रचंड जीत यह दर्शाता हैं कि भाजपा ने अपने रणनीति मे बेहतर परिवर्तन किया है ! यही कारण है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जो की भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल माना जाता था ! वहां पर भाजपा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ट रहा ! अब दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है ! कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि- दिल्ली मे आम आदमी पार्टी को हराना असंभव है, पर पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली मे आम आदमी पार्टी का विसर्जन तय है ! इसके कई कारण है ! यदि कुछ मुख्य बिन्दुओ पर प्रकाश डाले तो वो है, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविन्द केजरीवाल का जेल के अंदर से सरकार चलाना और जेल के बाहर आने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ! इस पूरे प्रकरण से जनता मे यह मैसेज गया है कि केजरीवाल वास्तव मे राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहे है ! दूसरा है उनके बेहद करीबियों ने इस बार उनसे दूरी बना ली है जो पिछले दो विधानसभा चुनाव मे उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम किये थे ! जैसा की उनके ही पार्टी के राज्य सभा सांसद स्वाती मालिवाल और उनके करीबी मंत्री कैलास गहलोत इत्यादि कई नाम है !

इन सबके अलावे इस बार दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई नई योजना दिल्ली मे लागू नहीं की है जिसके कारण जनता को सीधे तौर पर लाभ मिले ! दिल्ली मे जो भी योजनाएं है वो पिछले कार्य काल से ही चली आ रही है ! आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव मे जो घोषणा की थी उसपर भी कोई अमल नहीं किया गया ! ना तो दिल्ली के वायु प्रदूषण पर कोई ठोस कार्य हुए ना ही यमुना जी की स्थिति मे कोई सुधार हुआ ! ऊपर से शीशमहल के नाम से चर्चित मुख्यमंत्री आवास मे करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार्य का मामला और करोड़ों रुपये के उसमे लगे पर्दे ने दिल्ली की जनता के मन को कुरेदा है ! सरकार के लगभग सभी बड़े मंत्रियों पर भ्रष्टाचार्य के आरोप एवं लंबे समय तक जेल मे रहना इस बात को दर्शाता है कि-सब कुछ पहले जैसा समान्य नहीं रहेगा इस बार के चुनाव मे आप आदमी पार्टी के लिए !

एक तरफ यह भी माना जा रहा था कि काँग्रेस पार्टी का जो जनाधार था वह पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के तरफ रुख कर चुका है ! क्योंकि भाजपा के विपक्ष मे काँग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओ ने अपने वोट को बिखरने की जगह दिल्ली मे आम आदमी पार्टी को सहयोग करना ज्यादा उपयुक्त समझा था ! पर इस बार वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए है ! पिछले कुछ समय से दिल्ली प्रदेश काँग्रेस प्रमुख ने दिल्ली मे न्याय यात्रा की ! जो की केजरीवाल सरकार के नाकामियों को उज्जागर करने के उदेश्य से किया गया था ! इस यात्रा को काँग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओ ने पूरे दम खम से प्रदेश मे सफल बनाया ! इसके बाद डूसू चुनाव मे लंबे समय अंतराल के बाद काँग्रेस का अध्यक्ष बनना इस बात को दर्शाता है कि पार्टी कार्यकर्ताओ का हौसला अफजाई हुआ है और वो विधानसभा चुनाव भी पूरे मन से लड़ेंगे ! अभी पहलुओ पर यदि गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाता है की इस बार दिल्ली से आप के विसर्जन की पूरी संभावना बन गई है !

Grandstanding Over Governance: Failed Model of AAP

Bharat Sharma Advocate Delhi High Court

The Aam Aadmi Party (AAP) burst onto the political scene with promises of transparency, efficiency, and a people-first approach to governance. Today, its track record in Delhi and Punjab reveals a different story—one of misplaced priorities, administrative inefficiencies, and avoidable conflicts. From its much-hyped education and healthcare reforms to its unproductive confrontations with constitutional authorities, AAP has built a governance model that prioritises theatrics over tangible outcomes. Let us unravel the façade and explore the many cracks in AAP's governance.

Education: Revolution or Rhetoric?

AAP claims to have transformed education in Delhi, but this transformation often stops at the surface. While a few schools were revamped for a show, a large number of government schools still lack basic infrastructure like clean drinking water, functional toilets, and adequate classrooms. Allegations of corruption, such as inflated costs for classroom construction (₹25 lakh per room), further tarnish these achievements.

Punjab, under AAP's rule, has shown no visible improvement in its education system. Teacher shortages, inadequate infrastructure, and neglect of rural schools persist. The much-touted education revolution appears to be nothing more than a publicity campaign that overlooks the real challenges students and educators face.

Healthcare: Clinics for Cameras

AAP's mohalla clinics in Delhi are often showcased as a model for accessible healthcare, but their effectiveness remains questionable. Reports on staff shortages, long queues, and inadequate medical supplies paint a grim picture. Meanwhile, Delhi's public hospitals remain overcrowded and underfunded, with no significant investments to improve their capacity.

In Punjab, the healthcare system is in shambles. Drug addiction continues to plague the state, and public hospitals are ill-equipped to deal with the crisis. AAP's failure to expand rehabilitation centers or invest in healthcare infrastructure has left Punjab's citizens struggling for basic medical care.

Law and Order: Avoidable Chaos

Punjab's law-and-order situation has deteriorated under AAP, with an alarming rise in organised crime, gang wars, and drug trafficking. Despite pre-election promises of curbing the drug menace, AAP has failed to implement effective measures, leaving citizens feeling insecure.

In Delhi, law and order technically falls under the Union Government's jurisdiction. However, AAP's government has failed to complement law enforcement with robust urban safety measures. Initiatives like CCTVs and marshals in public transport, while heavily advertised, remain poorly implemented. The result is an environment where public safety, particularly for women, remains a serious concern.

Unproductive Confrontations with the LG

A hallmark of AAP's governance in Delhi has been its relentless and often unnecessary confrontations with the Lieutenant Governor (LG). While the LG is a constitutional authority tasked with overseeing Delhi's administration, AAP has repeatedly turned governance into a political battlefield.

Instead of focusing on governance, AAP has spent

years embroiled in turf wars, blaming the LG for every administrative challenge. From obstructing developmental projects to delaying policy implementation, these conflicts have stalled Delhi's progress. This constant state of confrontation, while serving AAP's political narrative, has diverted attention from real issues affecting Delhi's citizens. Governance is not about optics or public spats; it requires collaboration and consensus. AAP's unwillingness to engage constructively with the LG reflects poorly on its ability to prioritise Delhi's welfare over political theatrics.

Urban Development: Mismanagement and Stagnation

Delhi's urban infrastructure remains in disarray under AAP's rule. The Yamuna River, despite multiple promises of cleanup efforts, continues to suffer from toxic pollution. Air pollution levels in Delhi have reached hazardous levels, with no significant interventions from the government.

Public transport, especially the DTC bus system, is underutilised and poorly maintained, adding to the city's congestion woes. In Punjab, urban centres face challenges such as inadequate waste management and poor water supply, highlighting AAP's failure to focus on sustainable urban development.

Agriculture: Betrayal of Punjab's Farmers

Punjab's agrarian crisis has worsened under AAP's governance. Farmers face delayed procurement payments and rising input costs despite promises of MSP guarantees and debt relief. The government's failure to promote crop diversification or water conservation has left Punjab's farmers in a precarious situation. Instead of addressing these structural issues, AAP has focused on superficial measures, leaving the backbone of Punjab's economy—its farmers—feeling abandoned.

Social Welfare: Promises Without Progress

AAP's social welfare schemes, both in Delhi and Punjab, suffer from poor implementation and inadequate funding. In Delhi, schemes aimed at women's safety, senior citizens, and marginalised communities remain incomplete or ineffective. Punjab's rural development has stagnated, with villages lacking access to basic amenities such as healthcare, education, and roads. AAP's inability to deliver on these promises exposes its disconnect from the grassroots issues it claims to champion.

Corruption: The Clean Politics Myth

AAP's foundational promise of clean governance has been exposed as hollow. In Delhi, the liquor policy scam and allegations of corruption in classroom construction have raised serious questions about AAP's integrity. Similarly, in Punjab, senior leaders have faced corruption allegations, undermining the party's claims of transparency. AAP's governance is increasingly defined by the very practices it once opposed. The party's inability to uphold its promise of clean politics is a betrayal of the public trust.

Governance or Grandstanding?

AAP's governance model, both in Delhi and Punjab, is a cautionary tale of how political theatrics can overshadow genuine administration. While the party excels at public relations, its failures in education, healthcare, public safety, and urban development expose a lack of vision and competence.

The unnecessary confrontations with the LG in Delhi further highlight AAP's priorities: creating political narratives rather than solving real issues. These spats serve as a distraction from the party's administrative shortcomings and have cost Delhi valuable time and resources.

As Delhi gears up for the upcoming elections, the stakes have never been higher. This election is not just a contest between political parties but a critical juncture where the citizens of Delhi will decide between continued governance mired in controversies, confrontations, and unfulfilled promises, or a future that promises genuine development, collaborative governance, and strategic solutions to the city's pressing issues. With public safety, urban infrastructure, education, and healthcare at the forefront, voters must critically evaluate which party offers a vision that aligns with their aspirations for a stronger, safer, and more prosperous Delhi.

आम आदमी पार्टी विफल जल प्रबंधन: क्या कहते हैं आंकड़े?

विश्वजीत पाठक,
दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक अपनी संसदीय सीट लखनऊ के बारें में एक बार कहा था- "गोमती के किनारे बसा शहर पीने के पानी को तरसे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा?"

आज यही दुर्भाग्य दिल्ली वालों का है, जहाँ यमुना के किनारे बसी दिल्ली पानी को तरस रही है।

भीषण गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली जल संकट से जूझ रही होती है, उस वक़्त पूरे देश को शर्म आती है। देश की राजधानी में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा चिलचिलाती धूप के बीच पानी के लिए हर साल तरसता है। दिल्ली के VIP इलाकों में भी पानी के टैंकरों के पीछे-पीछे बच्चे और बूढ़े तक भागते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आने वाला पानी गंदा रहता है। दरअसल, यह पूरी अव्यवस्था की स्थिति क्यों है, इसकी पोल अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के खुद के दस्तावेज खोलते हैं।

केजरीवाल सरकार द्वारा जनता में रखे गए कागज ही बताते हैं कि बीते 9-10 वर्षों में दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली पानी आपूर्ति पर किए जाने वाले खर्चे भी कमी कर दी गई है। उस पर जितने खर्चे की योजना बन रही है, उसका आधा ही पैसा उसे दिया जा रहा है। इस बीच दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है।

राजधानी में पानी की माँग भी इन वर्षों में लगभग 30% तक बढ़ गई है, लेकिन धरना-प्रदर्शन वाली सरकार जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाई है। अरविन्द केजरीवाल की सरकार के दावों की पोल उन्होंने खुद दिल्ली के आर्थिक सर्वे में खोली है। इस आर्थिक सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं।

दूसरे राज्यों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने वाले केजरीवाल ने 2015 में स्थायी रूप से सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में जल आपूर्ति क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की है। इस क्षेत्र में उनका काम एकदम नगण्य है। यहाँ तक कि उनसे पहले सत्ता में रहने वाली शीला दीक्षित या बीजेपी के सरकारों के मुकाबले वह कहीं नहीं ठहरते।

दिल्ली को अलग-अलग स्रोतों पानी से मिलता है और इसे ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके भेजा जाता है। दिल्ली सरकार का 2023-24 का आर्थिक सर्वे बताता है कि वर्ष 2006 में दिल्ली में इस पानी साफ करने की क्षमता कुल 650 मिलियन गैलन/दिन थी। यह शीला दीक्षित सरकार के दौरान यह प्रति वर्ष बढ़ रही थी।

वर्ष 2015 तक आते आते यह क्षमता 906 मिलियन गैलन/दिन हो चुकी थी। यानी 2006 से 2013 के बीच दिल्ली में पानी साफ करने की क्षमता में 39% बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद केजरीवाल सत्ता में आ गए और मुफ्त पानी का वादा भी किया। 2015 के बाद से 2024 तक लगातार केजरीवाल लगातार सत्ता में हैं।

जहाँ 2015 में दिल्ली पानी की रोजाना माँग का 94% पानी साफ करने की क्षमता उसके पास थी तो वहीं 2024 तक आते-आते यह 73% हो चुकी है। यानी दिल्ली वर्तमान में जितना पानी चाहती है, उतना पानी साफ करने की उसके पास क्षमता नहीं है। वर्तमान में दिल्ली की एक चौथाई पानी की माँग पूरे करने के साधन उसके पास नहीं हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसका इलाज करने के बजाय अपने मंत्रियों को धरने पर बिठाने और दूसरे राज्यों पर दोष डालने में लगी हुई है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहाँ एक ओर लम्बे चौड़े वादे करती हैं तो वहीं जमीन पर काम करने के दौरान उसके सारे वादे हिरन हो जाते हैं। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वे ने ही बताया है कि जितना पैसे की योजनाएँ दिल्ली में प्रति वर्ष बनाई जा रही हैं, उतना खर्च नहीं हो रहा। पिछले तीन वर्षों में इसमें भारी गिरावट आई है। आर्थिक सर्वे के अनुसार, 2020-21 के दौरान दिल्ली पानी की कमी को पूरा करने के लिए ₹4004 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई थी। इसके मुकाबले ₹3584 करोड़ की ही धनराशि जारी की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹2951 करोड़ खर्च की मंजूरी दी गई थी लेकिन इस वर्ष मात्र ₹1892 करोड़ ही जारी किए गए। 2022-23 में तो जितना बजट मंजूर हुआ उसकी आधी धनराशि ही जारी की गई। 2022-23 में दिल्ली में पानी से सम्बन्धित सुविधाओं पर ₹6344 करोड़ के खर्चे की मंजूरी दी गई थी। इसकी तुलना में मात्र ₹3171 करोड़ ही जारी किए गए।

पानी साफ करने की नई क्षमताओं का विकास ना करना, सीवर व्यवस्था को ना बढ़ाना और पानी की आपूर्ति पर खर्च ना करना दिल्ली में वर्तमान जल संकट का बड़ा कारण है। दिल्ली की AAP सरकार इस नाकामी का ठीकरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर फोड़ कर बचना चाह रही है। उसके मंत्री केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं लेकिन जमीन पर काम नहीं कर रहे। मात्र जुबानी जमा खर्च करके ही काम चलाया जा रहा है।

जो दिल्ली दूसरे राज्यों को जल आपूर्ति कर सकती थी वो आज खुद हालकान है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और केजरीवाल के झूठे वादों की बारिश बरस रही है।

Populism vs. Progress: Evaluating BJP and AAP on Development Metrics

The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Aam Aadmi Party (AAP) are two political entities that have emerged with distinct ideologies and strategies to address India's development challenges. The BJP, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, has focused on national-level economic reforms, infrastructure development, and a broad agenda aimed at strengthening India's global position. AAP, on the other hand, has gained prominence primarily at the state level, with a focus on local governance, public welfare, and transparency, particularly in Delhi. This comparative review critically examines BJP's successes and AAP's failures on key development issues like economic growth, unemployment, infrastructure, social welfare, and fiscal management.

Sagar Saikia
PhD Research Scholar,
Department of CSE, NIT Meghalaya

1. Economic Growth and Investment

BJP's Success:

- National Economic Reforms: The BJP has successfully implemented several high-profile economic reforms, such as the Goods and Services Tax (GST), the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), and the introduction of the Make in India initiative. These have aimed at modernising India's economy and improving ease of doing business.
- Foreign Investment: The BJP-led government has attracted significant foreign direct investment (FDI) through pro-business policies, including the liberalization of key sectors like defense, retail, and aviation. The 'Atmanirbhar Bharat' (self-reliant India) program has focused on strengthening India's domestic manufacturing capacity while encouraging foreign investments.
- Infrastructure Investments: BJP's focus on infrastructure development, especially roads, highways, railways, and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC), has led to significant progress in national connectivity, boosting economic activity.

AAP's Failures:

- Limited Economic Strategy: AAP's economic focus has been largely centred on improving public services like education, healthcare, and water supply in Delhi. These initiatives have failed to enhance quality of life and have not contributed to broad-based economic growth or industrial development.
- Failure to Attract Investment: AAP has not been able to create a conducive environment for large-scale investment or industrial growth, especially compared to BJP's pro-business stance. Delhi remains reliant on the central government for funding, with limited local initiatives to boost industrialisation or expand the economy beyond public service sectors.
- Inconsistent Economic Policies: AAP's promises of economic reforms have remained fragmented. It has focused on welfare programs like subsidised electricity and water, but this has created fiscal strain and limited capacity for long-term investment in key sectors.
- While the BJP has succeeded in driving major economic reforms, attracting foreign investment, and improving infrastructure at a national level, AAP's performance on economic development remains largely constrained to empty promises of welfare and public service improvements in Delhi. AAP lacks a coherent economic strategy that can foster industrial growth or national-level investment.

2. Unemployment and Job Creation

BJP's Success:

- Job Creation through Infrastructure: Under the BJP government, the emphasis on large-scale infrastructure projects has led to job creation in sectors like construction, manufacturing, and transportation. The expansion of highways, railways, and the metro system has created millions of jobs.
- Skill Development Programs: The BJP launched various skill development initiatives such as the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), aiming to equip youth with employable skills and enhance employability.
- Support for MSMEs: BJP has worked towards providing credit and facilitating the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through the Mudra Yojana and other initiatives.

AAP's Failures:

- Limited Job Creation: While AAP has promised to provide public services, such as education, health, and utilities, these have not translated into significant job creation due to lack of implementation. AAP has made no concerted effort to create a broader employment ecosystem or address issues like youth unemployment or underemployment in the private sector.
- No Major Economic Initiatives: Unlike BJP's skill development and MSME-focused programs, AAP's economic policies have largely been centred on welfare schemes like free water and electricity. These programs have not addressed structural unemployment or created sustainable job opportunities.
- Public Sector Dependency: AAP's job creation efforts have largely been limited to government sectors like education, healthcare, and municipal services, leaving private sector employment largely untouched.

BJP's job creation strategy has been more holistic, focusing on infrastructure, skill development, and MSMEs, whereas AAP has largely relied on expanding the public sector and welfare schemes. AAP's narrow focus on public services has limited its ability to address large-scale employment issues effectively.

3. Infrastructure Development

BJP's Success:

- Massive Infrastructure Projects: Under the BJP, states has witnessed the rapid development of highways, railways, and the expansion of the metro system. The government has also made significant strides in developing smart cities, improving rural infrastructure, and upgrading airports.
- Digital Infrastructure: BJP's push for digital infrastructure has led to the successful rollout of initiatives like Digital India, aimed at providing internet connectivity and digital literacy across the country.
- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT): The BJP government has worked on transforming urban infrastructure and providing clean water, sanitation, and waste management to cities.

AAP's Failures:

- Limited Impact Beyond Delhi: AAP's infrastructure promise has been largely confined to improving Delhi's urban infrastructure—mainly roads, water supply, and public transport. However, its achievements in this area are limited to freebies in public service, with no significant, large-scale infrastructure projects that could have national or broader state-level impact.
- Public Transport Success: While the expansion of the Delhi Metro has been a notable achievement, it is a major credit to the central government.
- Underdeveloped Waste and Water Management: AAP has completely failed to ensure the supply of adequate and clean water to Delhi households.

4. Social Welfare and Public Services

BJP's Success:

- Welfare Programs: BJP has implemented several large-scale welfare schemes, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) for financial inclusion, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana for LPG connections to the poor, and Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) for affordable housing.

- Ayushman Bharat: The BJP launched Ayushman Bharat, a national health protection scheme that provides health coverage to over 100 million families, marking one of the world's largest healthcare schemes.
- Direct Benefit Transfers: The BJP government has implemented DBT to eliminate middlemen and corruption, delivering benefits directly to beneficiaries.

AAP's Failures:
- Fiscal Sustainability of Welfare: AAP's welfare programs, such as free water and electricity, have strained the city's finances. While these schemes have improved the quality of life for many, their long-term sustainability is in question due to budgetary constraints and the lack of substantial revenue generation.
- Healthcare Improvements: While AAP claims to have improved healthcare access in Delhi through Mohalla Clinics and expanding government hospitals, it is more on paper than on the ground. Most of such units are either dysfunctional or heavily underfunded and understaffed.
- It has not created a comprehensive national-level health policy or improved healthcare access for all marginalised communities.
- Education: The focus on upgrading infrastructure and teacher training has not fully addressed issues like overcrowding and unequal access to education in rural areas. The claims of improvement in education are overhyped and not supported by the data and independent audits.

BJP's welfare programs have been broader and more sustainable, with national reach and financial backing, whereas AAP's welfare schemes are primarily limited to Delhi and are less financially sustainable in the long run.

5. Fiscal Management and Budget Constraints
BJP's Success:
- Tax Reforms: The BJP government implemented GST, a major tax reform aimed at simplifying the taxation system and increasing government revenue. The introduction of digital tax collection systems has improved transparency.
- Financial Stability: BJP has worked to maintain fiscal discipline, even though challenges such as the COVID-19 pandemic disrupted public finances. However, the party has been able to secure large-scale infrastructure funding through partnerships with the private sector and international loans.

AAP's Failures:
- Reliance on Central Grants: AAP's fiscal management is largely dependent on central government funds, with limited capacity to generate independent revenue. The party's reliance on subsidies like free water and electricity has created significant fiscal strain.
- Debt Concerns: The Delhi government under AAP has faced criticism for its growing debt, which it struggles to manage alongside its ambitious welfare schemes.
- Sustainability of Subsidies: The unsustainable nature of AAP's welfare schemes—particularly free water, electricity, and subsidised healthcare—puts significant pressure on its budget. These schemes have not been backed by adequate revenue-generation mechanisms, making them difficult to sustain in the long term.

BJP has successfully managed fiscal policy with reforms like GST and improved tax collection, while AAP has struggled with fiscal sustainability due to its reliance on central funding and the long-term financial burden of its welfare programs.

In summary, the BJP's performance on key development issues is far-reaching, national in scope, and largely successful. In contrast, AAP's achievements, while commendable at the state level, have not addressed the broader developmental challenges facing India and have faltered due to fiscal mismanagement and limited vision beyond local governance.

केजरीवाल सरकार: झूठे वादों और विफल योजनाओं का दशक

मनुजम कुमार
स्वतंत्र टिप्पणीकार

कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए देशव्यापी सामाजिक आन्दोलन के प्रमुख चेहरा अरविन्द केजरीवाल ही रहे, जिन्होंने आगे चलकर आम आदमी पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ यमुना जैसे बड़े-बड़े वादे किए। हालांकि, पिछले एक दशक के अपने शासनकाल में इन प्रमुख मोर्चों पर अरविन्द केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की प्रमुख नीतिगत और कार्यात्मक विफलताओं ने आगामी चुनावों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलग तरह की राजनीति का दावा करके सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने राजनीति में झूठ, अमर्यादित आचरण और भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बहरहाल, अगर हम केजरीवाल के प्रमुख वादों की पड़ताल करते हैं, तो स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने दस वर्षों के शासनकाल में काम करने की बजाय आरोपों की राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया है।

बिजली और पानी की समस्याएं

दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। उन्होंने अपने चुनावी वादों में बिजली और पानी के मुद्दों को प्राथमिकता दी थी। लेकिन आज, वर्षों बाद भी, जनता इन्हीं बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। वादे तो बड़े-बड़े किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है।

केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि दिल्ली में सस्ती और निरंतर बिजली मुहैया कराई जाएगी। शुरुआत में कुछ योजनाएं लाईं गईं, जिनमें सब्सिडी देकर बिजली के बिल कम किए गए, लेकिन यह कदम लंबे समय तक टिक नहीं पाया। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में नियमित बिजली कटौती हो रही है। गर्मी के मौसम में बिजली संकट चरम पर रहता है। ऊपर से दिल्ली सरकार पर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं। सब्सिडी का लाभ हर किसी तक नहीं पहुंचता और इसमें पारदर्शिता की कमी नजर आती है।

अचरज इस बात का भी है कि दिल्ली सरकार ने दस वर्षों में बिजली कम्पनियों की ऑडिट कराने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या यह केवल एक चुनावी स्टंट था या वास्तव में जनता के हितों के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई थी? सबको पीने का स्वच्छ पानी जैसे नारे तो खूब गूंजे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्थिति अलग है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी पानी की समस्या विकराल है। पानी या तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, या फिर उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि लोग इसे इस्तेमाल करने से डरते हैं। टैंकर माफियाओं को लगाम लगाने के वादे के साथ आए केजरीवाल आज टैंकर माफियाओं से मिलीभगत के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही यमुना नदी की सफाई का वादा भी केजरीवाल सरकार के चुनावी एजेंडे का हिस्सा था। लेकिन यमुना का हाल दिन-ब-दिन बदतर होता जा रहा है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग आज भी साफ पानी के लिए संघर्ष

कर रहे हैं। कई बार टैंकर माफिया का बोलबाला देखा गया है, जिससे यह साफ है कि पानी की आपूर्ति की दिशा में दिल्ली सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं।

केजरीवाल सरकार ने अपनी योजनाओं का प्रचार तो खूब किया, लेकिन उनके कार्यान्वयन में कई खामियां नजर आईं। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान न देना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है।
जहां एक ओर सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटती है, वहीं दूसरी ओर जनता के सवालों का जवाब नहीं मिलता। क्या वादों का यह सिलसिला केवल वोट बैंक तक सीमित था?

शिक्षा क्षेत्र में खामियां

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा किया और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया। सरकारी स्कूलों के सुधार, शिक्षा बजट में वृद्धि और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने जैसे बड़े वादे किए गए। लेकिन जब इन वादों को ज़मीनी हकीकत पर परखा जाता है, तो कई खामियां और कमजोरियां उभर कर सामने आती हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार का प्रचार जोर-शोर से किया गया। कुछ प्रमुख स्कूलों की चमकती इमारतें और साफ-सुथरे परिसर को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये स्कूल दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते। हजारों स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई जगह बच्चों को टूटी हुई कुर्सियों और बरसात में टपकती छतों के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती है। लड़कियों के लिए शौचालय की कमी और पीने के पानी की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। ये बुनियादी खामियां केवल वादों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कार्यों से दूर हो सकती हैं, जो अभी भी नहीं दिखते।

शिक्षकों की कमी दिल्ली के शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। सरकारी स्कूलों में कई पद खाली पड़े हैं, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो शिक्षक हैं, उन्हें पढ़ाने के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों में उलझा दिया जाता है। इसके अलावा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और उन्हें नई शिक्षण विधियों से लैस करने के प्रयास भी अपर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों के सर्वांगीण विकास की उम्मीद करना बेमानी है।

पढ़ाई के स्तर की बात करें तो केजरीवाल सरकार का जोर परीक्षा परिणाम सुधारने और छात्रों को पास कराने पर अधिक है, बजाय उनके ज्ञान को गहरा और व्यावहारिक बनाने के। कई स्कूलों में छात्रों को जीवन कौशल और आधुनिक तकनीकों की शिक्षा नहीं दी जा रही है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब पाठ्यक्रम में रचनात्मकता और नवाचार का स्थान केवल रटने की प्रक्रिया ले लेता है।

निजी स्कूलों की मनमानी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। केजरीवाल सरकार ने फीस वृद्धि को नियंत्रित करने और अभिभावकों को राहत देने के दावे किए थे, लेकिन हकीकत में निजी स्कूल आज भी मनमानी कर रहे हैं। फीस वृद्धि और अतिरिक्त शुल्कों ने अभिभावकों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। सरकारी स्कूलों के सुधार में असफलता ने निजी स्कूलों को और मजबूत किया है, जिससे शिक्षा आमजन के लिए एक महंगा सौदा हो गया है।

डिजिटल शिक्षा के मामले में भी दिल्ली सरकार के प्रयासों में कमी साफ दिखती है। महामारी के दौरान जब ऑनलाइन शिक्षा जरूरी हो गई थी, तब अधिकांश सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का अभाव था। यह स्थिति यह दिखाती है कि डिजिटल शिक्षा का दायरा कुछ चुनिंदा स्कूलों तक सीमित रहा और बड़ी आबादी इससे वंचित रही।

सरकार ने शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी का दावा किया, लेकिन इस बजट का बड़ा हिस्सा प्रचार और कुछ मॉडल स्कूलों पर खर्च हुआ। शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि का लाभ समग्र रूप से सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाया। जब तक इस बजट का उपयोग पारदर्शी और व्यावहारिक तरीके से नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा सुधार के वादे केवल कागजों पर ही रहेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविकता: वादों और हकीकत के बीच की खाई

इसी क्रम में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाने के बड़े-बड़े दावे किए। "मोहल्ला क्लीनिक" से लेकर सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार तक, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाया। इन दावों ने न केवल जनता का ध्यान खींचा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन जब इन वादों को हकीकत की कसौटी पर परखा जाता है, तो कई खामियां और चुनौतियां सामने आती हैं। आज हकीकत यह है कि 5,590 करोड़ के आवंटित बजट में 24 प्रस्तावित अस्पतालों को कागज तक ही समेट दिया गया।
केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मोहल्ला क्लीनिक थी, जिसे "स्वास्थ्य सुविधाएं घर तक पहुंचाने" के उद्देश्य से शुरू किया गया। शुरुआती दिनों में यह योजना सराहनीय लगी, लेकिन समय के साथ इसकी खामियां उजागर होने लगीं और समय के साथ-साथ कभी जांच तो कभी नकली दवाईयों के नाम पर यह भारी भ्रष्टाचार का क्लिनिक बनकर रह गया है। मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टरों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और अपर्याप्त सुविधाओं ने इसके प्रभाव को सीमित कर दिया। ये क्लीनिक शुरुआती जांच और सामान्य दवाएं तक देने में विफल हैं, जबकि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मरीजों को बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार का दावा भी किया गया, लेकिन यह सुधार बड़े पैमाने पर प्रभावी नहीं हो पाया। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमी, लंबी कतारें और मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तरों का अभाव अब भी एक बड़ी समस्या है। कई अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी उपकरण या तो उपलब्ध नहीं हैं या खराब पड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां इलाज बेहद महंगा है। सरकार ने स्वास्थ्य बजट बढ़ाने का दावा किया, लेकिन इस बजट का उपयोग स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण देने में पर्याप्त रूप से नहीं किया गया।

कोविड-19 महामारी ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविकता को उजागर कर दिया। महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी देखी गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन गई थी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस संकट ने दिखाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में "आपातकालीन तैयारी" की कितनी कमी है। महामारी के दौरान मोहल्ला क्लीनिक पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुए, क्योंकि ये गंभीर मामलों को संभालने में सक्षम ही नहीं थे।

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग और टेलीमेडिसिन की बात करें, तो यहां भी केजरीवाल सरकार प्रभावी नहीं रही। महामारी के दौरान जब डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब यह सुविधा केवल कुछ ही अस्पतालों और क्षेत्रों तक सीमित रही। गरीब और तकनीकी रूप से पिछड़े वर्गों तक यह सेवा पहुंच ही नहीं पाई।

दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता की भी कमी देखने को मिलती है। 'आयुष्मान भारत' जैसी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से इनकार कर दिल्ली सरकार ने अपनी स्वास्थ्य नीतियों को प्राथमिकता दी, लेकिन इसका लाभ हर वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। निजी अस्पतालों पर नियंत्रण की भी भारी कमी है, जहां इलाज की लागत आसमान छू रही है।

अरविन्द केजरीवाल एक बार फिर से जनता की अदालत में जा रहे हैं और एक बार फिर झूठे वादों की बुनियाद पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार के वादे और उनकी हकीकत के बीच की खाई ने जनता को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं के दावे, जब जमीनी हकीकत से टकराते हैं, तो अधूरे नजर आते हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ा मानदंड है और शायद अब समय आ गया है कि जनता उनसे वही सवाल पूछे, जो उन्होंने अपने चुनावी अभियान में दूसरों से पूछे थे।

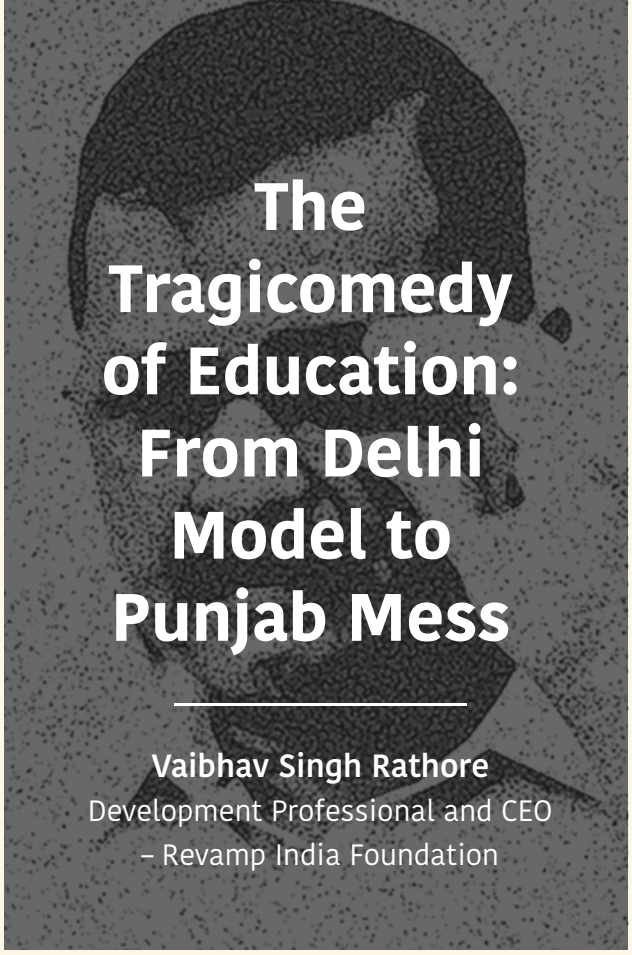

The Tragicomedy of Education: From Delhi Model to Punjab Mess

Vaibhav Singh Rathore
Development Professional and CEO
– Revamp India Foundation

The Aam Aadmi Party (AAP), after its victory in March 2022 in Punjab, was expected to implement an "education revolution" analogous to the much-propagated “Delhi model”. However, today, Punjab's educational system is not only in a state of stagnation but has also turned into a topic of ridicule. The policies (or one may say their lack) indicate that the present administration may view education as more of a joke than a top priority.

Replicating the “Delhi Model”: Punjab’s Misfit Experiment

The AAP has come under heavy fire for its attempt to introduce the Delhi educational model to Punjab. Despite the Delhi model’s supposed merits, critics contend it ignores Punjab’s difficulties. In national surveys, Punjab has continuously fared better than Delhi, especially in language and maths. Punjab outperformed Delhi in terms of overall student achievement in the National Achievement Survey (NAS) 2021, demonstrating that a general adoption of the Delhi model was ill-advised.

However, under Chief Minister Bhagwant Mann, the AAP government moved rapidly forward, putting public relations ahead of real educational changes. The outcome? Punjab’s education system is in ruins due to policies intended to duplicate the failure of Delhi’s story.

The Abandoned Projects

The government’s withdrawal from the Prime Minister’s Schools for Rising India (PM-SHRI) initiative is a stark illustration of its indifference. Punjab’s schools would have received ₹515 crore in central financing through this program. The government chose to opt out instead, depriving 241 schools of vital funding for improvements to their infrastructure.

Schools of Eminence: Promises vs. Performance?

With certain publicity, the AAP government declared that “Schools of Eminence” would be established for grades 9–12. 118 government schools were to be converted into cutting-edge establishments. However, only 14 of these schools will be open by the middle of 2024. Thus, critics highlight that these are only superficial improvements, and even these confront significant infrastructure issues.

Over 1.5 lakh applications were received for 20,000 seats. This enormous demand highlights Punjab’s severe lack of high-quality educational opportunities. However, rather than growing the program to accommodate public needs, the administration appears content with envisioning opportunities.

The Fiscal Management

The government allocated money in the 2024–2025 budget to turn 100 government senior secondary schools into “Schools of Brilliance” and 100 elementary schools into “Schools of Happiness.” Great names, yes. However, where is the foundation? Many rural schools in Punjab continue to struggle with deteriorating classrooms, a dearth of teachers, and a lack of basic facilities like clean drinking water and working toilets.

The government has spent much money promoting these programs rather than dealing with these major issues. One can question if the Chief Minister would rather create schools or pursue a comedic career again.

The JEE Mains Triumph: The Silver Lining?

The fact that 158 students from government schools qualified for JEE Mains in 2024 was an encouraging development. Nevertheless, structural issues obscure even this accomplishment. Private

coaching facilities and tuition fees, not the government, are primarily responsible for the credit.

A Litany of Unmet Policy Objectives

The AAP government has consistently failed to keep their promises. For example:

- Teacher Training: Although plans to train teachers overseas have been announced, there isn't any concrete proof that they have been carried out successfully.
- Infrastructure Development: There has been little progress on the pledge to construct 13,000 classrooms and install Wi-Fi in schools.
- Boundary Walls: There is simply a paper proposal to build 1,200 kilometres of boundary walls around 8,000 schools.

The Real State of Affairs

A startling reality is shown by data from the Punjab School Education Department: There are still over 5,000 open teaching posts in government institutions. Basic facilities like fans and comfortable chairs are lacking in many schools. In rural areas, dropout rates are still on the rise, particularly among girls, despite government assurances.

The Chief Minister frequently shifts the blame to the national government or earlier administrations when faced with these figures. However, the fact remains that the AAP has not produced any noticeable outcomes in their two years in office.
The Satirical Reality of Education in Punjab

The irony is unavoidable: this educational tragicomedy is now run by a government headed by a former comic. The informal and relaxed leadership style of Bhagwant Mann seems unable to tackle Punjab's long-standing educational issues.

The Chief Minister appears to emphasise publicity stunts and social media presence more than education. CM Mann might think that witty one-liners can replace well-written policies. However, this strategy is neither amusing nor a solution to the difficulties teachers and students face due to a lack of resources.

A key component of any government's priority needs to be education. It serves as the cornerstone around which a state's future is constructed. However, in Punjab, it is now merely a political theatre prop and an afterthought.

There is no denying the evidence. The AAP government has disregarded the fundamental requirements of Punjab's education system. The current administration exhibits a concerning lack of commitment, as evidenced by its abandonment of key projects, broken pledges, and preference for public relations over real reform.

Learning from UP's Educational Success: A Model for Punjab's Reform

The Punjab government can learn critical lessons from UP's successful educational initiatives. Unlike Punjab's PR-focused approach, UP has demonstrated tangible progress through systematic reforms and effective utilisation of resources. Most notably, UP secured significant central funding through the PM-SHRI project to upgrade over 300 schools with advanced facilities. At the same time, Punjab opted out of this scheme, losing ₹515 crore in potential funding. UP's Operation Kayakalp transformed over 1.3 lakh schools with smart classrooms and essential infrastructure, addressing similar challenges that Punjab currently faces with deteriorating facilities and lack of basic amenities.

UP's success also stems from its comprehensive approach to staffing and monitoring. While Punjab struggles with 5,000 vacant teaching positions, UP recruited over 1.5 lakh teachers between 2017-2023 and implemented effective teacher training programs. The state's use of a centralised digital dashboard for monitoring school performance and maintaining accountability offers a clear template for Punjab to improve its governance structure. Additionally, UP's focus on vocational training through the One District One Product initiative and targeted support for girls' education through programs like Kanya Sumangala Yojana provides a blueprint for Punjab to address its rising dropout rates and create more employment-ready graduates.

City Beautiful in Decline: AAP's Failed Governance in Chandigarh

Vaibhav Gupta
Convenor, Good Governance Department,
BJP Chandigarh

The party that rose to power in Delhi on an anti-corruption narrative has ironically become synonymous with corruption and political expediency. In both Delhi and Punjab—states that share proximity to the picturesque city of Chandigarh—the Aam Aadmi Party (AAP) and the Congress routinely accuse each other of being "scamsters" and "the most corrupt." Yet, in Chandigarh, driven solely by the lust for power, these same adversaries have joined forces to elect the Mayor and Deputy Mayors of the city.

Much like in Delhi and Punjab, AAP's promises during the Municipal Corporation elections in Chandigarh included a slew of freebies such as free water supply and Mohalla clinics in every sector. However, as the tenure of AAP's first Mayor in Chandigarh nears its conclusion, the promises remain conspicuously absent on the ground. The glaring gap between rhetoric and reality speaks volumes about the priorities of the so-called "anti-corruption" crusaders. The promise of free water supply, Mohalla Clinics, and free parking remains unfulfilled, exposing the gap between AAP's rhetoric and its performance. Chandigarh, a city known for its planned infrastructure and aesthetic appeal, now faces a crisis of

mismanagement. Roads are poorly maintained, public spaces are losing their charm, and healthcare infrastructure remains stagnant despite grand promises. This deterioration is a direct consequence of AAP's inability to prioritise and allocate resources effectively.

In stark contrast, the Central Government, under the visionary leadership of Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India, has not only launched but is actively implementing the 24x7 Water Supply Scheme in Chandigarh, which was recently inaugurated by the home minister Shri Amit Shah. Meanwhile, the AAP-led administration has failed to deliver even a single Mohalla Clinic in the city, despite its lofty promises.

Another major election promise by AAP in Chandigarh was the provision of "free-of-cost" parking facilities. Ironically, even after a year of AAP and Congress jointly securing the Mayor's position, they have failed to make the parking in front of the Municipal Corporation building "free of cost." This glaring inaction underscores the party's inability to deliver on its commitments.

The party that pledged a "Good Governance" model for Chandigarh has failed to uphold even basic governance principles within its ranks. It is easy to make grand promises for votes and then conveniently shift the blame to previous regimes when those promises prove impractical. Such actions are nothing less than "public fraud" perpetrated by the AAP in Chandigarh.

The AAP Mayor has been prioritising non-essential agendas, diverting resources away from critical issues, leading to a noticeable decline in the city's sanitation, cleanliness, and overall public health.

The constant internal conflicts and party-driven mandates have further eroded the effectiveness of the local government. AAP Councillors, instead of collaborating to address pressing civic issues, are often seen engaging in politically motivated clashes within the House. This inability to foster a cooperative environment has stalled decision-making processes, leaving critical projects either delayed or abandoned altogether.

One of the most glaring issues is the lack of financial prudence. Instead of investing in long-term developmental projects, the administration has diverted funds to non-essential agendas, prioritizing optics over substance. The overemphasis on freebies has led to a strain on the limited budget of the Municipal Corporation, crippling its ability to address critical needs. Such populist measures may win short-term applause, but they undermine the fiscal stability required for sustainable governance. The practice of offering "freebies" at the expense of public funds poses a serious threat to economic growth. When such unrealistic promises are made at the local level, where budgets are already constrained, they not only jeopardise the city's basic needs but also tarnish its overall reputation. Chandigarh, celebrated for its beauty and meticulously planned infrastructure, risks losing its iconic status as the "City Beautiful" if this culture of misgovernance and populist gimmicks continues unchecked.

To preserve the city's legacy, it is imperative to focus on pragmatic governance that prioritises sustainable development over hollow promises. Moreover, the "freebie culture" being propagated by AAP is not a sustainable governance model. While such promises may provide temporary political mileage, they erode the financial stability of local bodies and divert attention from long-term developmental goals. Chandigarh's citizens expect transparency, accountability, and efficient management of public resources. Leadership that fails to deliver these essentials not only compromises the quality of life for its residents but also tarnishes the city's reputation as a model urban centre.

The residents of Chandigarh deserve better—a governance model that focuses on fulfilling the city's basic needs while also planning for its future growth. Effective leadership is about balancing fiscal responsibility with public welfare, not indulging in political theatrics or short-term gains. If Chandigarh is to maintain its position as a leading city in India, its governance must rise above party politics and focus on genuine progress.

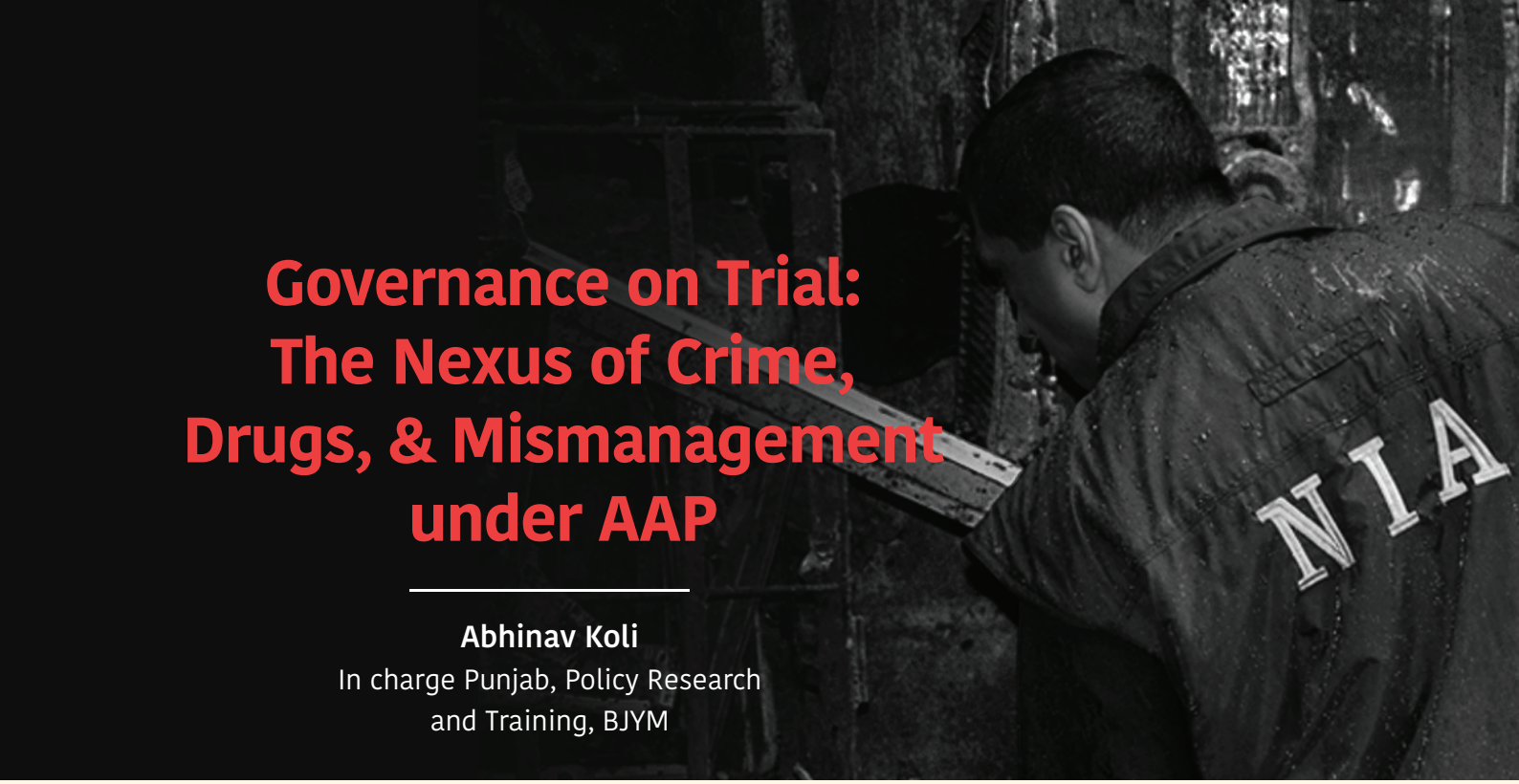

Governance on Trial: The Nexus of Crime, Drugs, & Mismanagement under AAP

Abhinav Koli
In charge Punjab, Policy Research and Training, BJYM

The state of law and order in Punjab and Delhi, under the governance of the Aam Aadmi Party (AAP), has increasingly come under scrutiny. Recent developments and reports, including the National Investigation Agency's (NIA) Operation Dhvast, have painted a grim picture of organised crime thriving within the jurisdictions of these regions. This article delves into the burgeoning nexus of gang operations, drug trafficking, and administrative loopholes, raising pertinent questions about governance and accountability.

Operation Dhvast: Exposing the Gangster-Terror Nexus

In a major crackdown, the NIA recently conducted Operation Dhvast, raiding over 325 locations across India to dismantle the gangster-terror nexus. This operation uncovered a disturbing reality: top gangs such as the Lawrence Bishnoi gang, Neeraj Bawana gang, Kaushal Chaudhary gang, and Jaggu Bhagwanpuria gang were operating seamlessly from the confines of jails in Punjab and Delhi. The press release by the NIA highlighted how these criminal networks had turned prisons into safe havens, using them as command centres to orchestrate extortion, murders, and drug trafficking. The nexus extends beyond gang rivalries, with connections to terror outfits and transnational drug cartels. Investigative reports reveal that these gangs have amassed illicit wealth worth hundreds of crores, funding further criminal enterprises. These findings underscore a systemic failure in curbing illegal activities, exacerbated by alleged administrative lapses in managing correctional facilities.

Punjab: A Breeding Ground for Drugs and Organised Crime

Punjab's association with drug trafficking is long-standing, but the situation has worsened in recent years. The state has become a hotspot for heroin smuggling, often referred to as the "factory" of drugs in India. The porous border with Pakistan facilitates the influx of narcotics, which are then distributed across the country through well-organized networks. According to a report by the Narcotics Control Bureau (NCB), Punjab accounts for over 60% of drug seizures in India, highlighting the scale of the problem.

The rampant drug trade has fueled organised crime, with gang wars becoming a regular occurrence. High-profile murders, such as those of Punjabi singer Sidhu Moosewala, Vicky Middukhera, and kabaddi player Sandeep Nangal Ambia, have highlighted the deep entrenchment of gang culture in Punjab. These killings, linked to rivalries among the aforementioned gangs, reflect the brutal and unchecked rise of criminal enterprises in the state. Media investigations have also revealed how these

gangs recruit young men, often addicted to drugs, to carry out heinous crimes in exchange for money or protection.

Adding to the controversies, gangster Deepak Tinu, a close aide of Lawrence Bishnoi, managed to abscond from CIA custody in Punjab. This blatant security lapse further underscores the administrative failures in handling high-profile criminals. The incident received widespread media attention, with The Tribune and Hindustan Times questioning the credibility of law enforcement agencies in the state.

Delhi: The Capital's Underbelly

Under AAP governance, Delhi is grappling with its own challenges. The Tihar Jail, India's largest correctional facility that comes under the Delhi government, has become infamous for being a hub of organised crime. Investigations reveal that gangs operating from within Tihar's walls are involved in extortion, land grabbing, and contract killings.

The recent NIA raids shed light on how prison officials have failed to curb the influence of these gangsters. Smuggling of mobile phones, drugs, and other contraband items into jails enables gang leaders to maintain their operations seamlessly. For instance, in 2023 alone, over 2,000 mobile phones were confiscated from inmates in Tihar, according to a report by the Delhi Police. Despite claims of stringent reforms, the ground reality indicates a lack of effective oversight and accountability.

Governance and Accountability: A Question of Priorities

The AAP's governance model, often lauded for its focus on education and healthcare, seems to falter significantly regarding law and order. The party has failed to prioritise security measures, allowing criminal networks to flourish. The management of prisons, in particular, has been a glaring loophole. Reports of corruption among jail officials and lack of surveillance have further emboldened criminals.

Moreover, the lack of a comprehensive strategy to tackle drug trafficking in Punjab raises questions about the state government's commitment to eradicating this menace. While the Punjab Police have conducted numerous raids and arrests, the scale of the problem demands a more coordinated and stringent approach involving both state and central agencies. Reports from 2024 also indicate a 15% increase in gang-related crimes compared to the previous year, further underscoring the deteriorating law and order situation.

The Broader Implications

The unchecked rise of organised crime and drug trafficking in Punjab has far-reaching implications. Economically, it drains resources and discourages investment. Socially, it creates an environment of fear and insecurity, particularly among the youth, who are often drawn into the vicious cycle of drugs and crime. Politically, it erodes public trust in governance and the rule of law.

The gangster-terror nexus, as exposed by Operation Dhvast, also poses a significant threat to national security. The involvement of international drug cartels and terror outfits in these operations underscores the urgent need for awareness of this issue. Intelligence reports suggest that funds generated through organised crime have been used to finance terror activities across the border, further escalating the threat.

The AAP government has failed to curb the rise of organised crime and drug trafficking, raising serious questions about its governance and administrative capabilities. As the situation worsens, the need for decisive and effective action becomes increasingly urgent.

AAP Governance Model: False Promises and Flawed Delivery

Tirthankar Jana
IT Engineer

Arvind Kejriwal could be mistaken for being a real-life Anil Kapoor of Nayak fame. An all-action common man cum outsider turned chief minister, fighting against the established corrupt elite and attempting to make a mark and impact on the “aam aadmi”, it was one of those few moments in Indian political history that there was such a convergence of reel and real. Okay, sorry to disappoint if you are a romantic and eternal optimist- No, real did not meet real; rather, the real has an uncanny similarity with the original reel chief minister of Nayak. Kejriwal had impeccable credentials, was a middle-class IIT graduate serving in the Indian Revenue System, and was a Magsaysay award winner without sacrificing his normal attire; he was what many in the middle-class in India aspired to be. And when he and his colleagues launched India Against Corruption and promised a different brand of politics, it promised a lot but turned out to be a damp squib.

Kejriwal seemed to be a man in a hurry, from delivering everything the common man wanted in his daily life to punishing the corrupt as if he was being sent to fulfil it and play the role of David, the greatest underdog ever. And as a result, he and his party made a litany of promises to Delhi, which he rinses and repeats before every election.

Let's start with water, one major poll plank of AAP. "Hum Dilli mein saaf aur free paani denge" was the promise. AAP has been promising the same thing before Delhi goes to polls in these last 12 years. In 2014, they had promised clean and free pipe water within 5 years. The reality is Delhi Jal Board, which the AAP governs, has recorded a net loss of Rs 73630 cr in 10 years. So, forget the promise of clean water; images of people rushing to get water from tanks and dirty water from taps have gone viral, a sad indictment of the national capital.

They have also promised the women of Delhi the "Mahila Samman Yojana". However, their chequered history of not being able to fulfil their similar promise in Punjab, citing the Model Code of Conduct and financial mismanagement in the state, does not inspire much confidence that they would walk the talk. Women's safety was something they had hedged their bets on and had promised an emergency button in mobile phones that would alert the authorities, but there has been nothing to show in 2024.

There were lofty, tall promises of elevating the infrastructure of Delhi on the lines of international standards and promised to spend Rs 400 crore, yet the condition of roads in the capital city is no secret to anyone and squarely put the blame on the Lieutenant Governor(LG). Beautification of the city was promised by turning the city into a 380 numbered lakes city, yet the brutal truth is it requires a downpour for the entire city to be drowned, with one image of a DTC bus caught in the rains near Minto Bridge being a meme material.

Travel in metro and DTC bus rides were supposed to be made free for women, yet a 2017 Hindustan Times report claimed there were governmental struggles to fix the transport issues, and an India Today report highlighted an alarming lack of buses, which contradicted a Supreme Court ruling which had directed 10000 buses, whereas on the ground there are only 7683 buses. The lack of public transport buses led to the rise of private vehicles, resulting in alarming pollution levels, which brought us to the failure of the much-hyped Odd-Even scheme and the stubble burning in Punjab.

"We will eradicate pollution" was promised in 2019; the reality of the situation is stark and concerning, with AQI levels high with the city being an echo chamber and toxic foam in the Yamuna, contrary to spending Rs 6856 crore to beautify and clean the river. People are aware of the Ghazipur landfill, which is another reason Delhi keeps being in the news for the wrong reasons. It has gotten worse despite, you know, all the promises made, inevitably before election season, of finding a permanent fix. It looks like a workaround is not even in sight. Then comes their pet project, the Mohalla Clinics, which the AAP government claims was applauded by foreign-based media outlets. The harsh truth is the Mohalla Clinics are in terrible condition, bereft of doctors and medical equipment. And, of course, the mammoth scale mismanagement during COVID when government hospitals had run out of Oxygen supply.

The above claims of big talk and less or no delivery have been a catastrophic chain of bad governance that has plagued Delhi. Winning handsome verdicts was a show of faith in this party, which has come to nought. With the municipal bodies also under AAP now, any attempt to pass the buck will find no takers. Delhi has been misruled and deserves better. BJP has a solid 37-38% fixed vote share in the city, which has always stood by it in any election. The situation and ground are fertile and ripe for a change in guard. BJP must reach out to the people, highlighting false promises and words of AAP that have not translated into deeds. BJP must talk about its plan to solve the problems that people have been facing in their daily lives.

A Cautionary Tale: How AAP's Policies Undermine Delhi's Future

Pranjal Chaturvedi
Doctoral Fellow at
Bennett University

The Aam Aadmi Party (AAP), under the leadership of Arvind Kejriwal, has been a significant force in Delhi's political landscape since its inception, though failing to make any mark in Lok Sabha elections. The people mandated Bhartiya Janta Party to be the single largest party in 2013 - Delhi's state Assembly Elections with 31 seats, just 5 seats short of the majority mark and the Aam Admi Party with 28 seats. The people disgruntled with the Indian National Congress brought down Congress to just 8 seats. The entire AAP campaign was exposing the corruption of INC, but by flipping sides, AAP established an alliance with the Indian National Congress and formed a government in Delhi. Arvind Kejriwal, who is also the National Convenor of AAP, became chief minister. Just within 49 days, the AAP severed its alliance with INC and entered an electoral truffle alone and formed the government with impressive marks in 2015, securing 67 seats. Again, in the 2020 election results, the AAP with reduced seats obtained 62 seats, though securing a clear majority. However, BJP maintained a landslide victory in Lok Sabha Elections, with 7-0 consecutively in 2014, 19 and 24.

While the party has garnered praise for its self-bolstering claims and favouring media for its focus on education, healthcare, and public services, due to window-dressing of the primary healthcare (mohalla-clinis) and schools, its economic management has been a subject of intense scrutiny and criticism. Even the (mohalla-clinis) flagship health care scheme of the Delhi Government is not without the allegations of financial irregularity. It is alleged that some Mohalla Clinics allegedly ordered and ran lakhs of "fake" pathology and radiology tests on non-existent patients; if correct, it would be irregularity worth hundreds of crore rupees. The Delhi education model is also a hyperbola, created by the leaders of AAP, the ballon of which got busted by the affidavit of the Delhi Government, filled in response to a PIL filed at Delhi High Court. The petition highlighted that the schools have been teaching students for 2 hours per day only or calling them on alternative days as they don't have enough infrastructure. The teacher-to-student ratio is alarmingly high, reducing the time expected of each student in schools.

The Aam Aadmi Party (AAP) is a byproduct of the Anti-Corruption Movement, which sprung from the Anna Protest in Delhi. Arvind Kejriwal, at the helm of an anti-corruption protest against the then incumbent congress government, decided to form a political party to participate in the electoral exercise, against the willingness of his Political Guru, Anna Hazare. Out of the desired symbols of ‘Broom’, ‘Candle’, and ‘Tap’, the election commission on the 1st day of August 2013 allotted the Broom as the election symbol to the Aam Admi Party. Broom was seen as the epitome of clean and corruption-free politics in Delhi.

The official website of APP claims Broom has ‘become a symbol of the party's core promise of cleaning up the system – be it from corruption, communalism, criminalisation and other evils of politics", rather contrary to the claimed values and principles APP practised every action, against which it stood at the budding stage, to acquire peoples mandate. The Himalayan paradox is Arvind Kejriwal, the poster boy of the anti-corruption movement, national convenor of AAP and the three-term Chief Minister of Delhi, had to resign from the chair of Delhi Chief Minister due to being incapacitated by the Bail order passed by Hon'ble Supreme Court of India, stating that “he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance/ approval of the Lieutenant Governor of Delhi ... He will not interact with any of the witnesses and/or have access to any official files connected with the case..." in the case Arvind Kejriwal Vs. Directorate Of Enforcement, Dating 10 May, 2024.

AAP's economic policies have often been characterised by populist measures aimed at garnering public support and votes devoid of any long-term growth and infrastructural facilitation. Among populist political moves, the most robustly appropriated notable initiative has been the

provision of free water and electricity to the residents of Delhi. Under the Aam Admi Party's decade-long rule, Delhi's revenue collection has steadily declined, falling from 5.4% of GDP to 3.9%. This decline has been attributed to inefficiencies in tax collection and administration, a lack of innovation in revenue generation, and over-reliance on short-term electoral strategic gain. The impact of this drop has been far-reaching. A lack of farsightedness has limited the city's capacity to invest in critical infrastructure and public services. The Delhi High Court, in November 2024, voiced similar concerns. A bench headed by Chief Justice Manmohan reprimanded the Aam Admi Party government for prioritising freebie-driven schemes over necessary infrastructural development required in Delhi.

Another contentious and critical issue has been the government's growing dependence on debt to finance its populist measures and revenue expenditure. In 2015–16, the Delhi government had a budget surplus of 1.56%, but this fiscal balance has since tipped into deficit, reducing the financial soundness of the Delhi government. The city has increasingly relied on borrowing to meet its expenditure needs, culminating in a proposed loan of ₹10,000 crores from the National Small Savings Fund for the financial year 2024–25—ironically, just months before the elections. This trend of escalating debt raises valid questions about the city's long-term financial health and its ability to manage its obligations responsibly. The bizarre is Delhi government's advertisement spending increased by 4,200% from 2012 to 2022. When the world was spending every single penny with utmost caution and care of COVID–19, the Delhi government spent 293 Crore on advertisements, which is a 93.2 Crore surplus than what the Delhi government spent in 2019 – 20 (pre-COVID year).

Allegations of financial mismanagement have further complicated the narrative of Aam Admi Parties governance. Accusations of misusing taxpayers' hard-earned contributions and engaging in questionable financial practices have eroded public trust in the incumbent political leadership heading the Delhi government. For instance, the government's decision to extend honorariums to Imams and Muezzins not directly under the Waqf Board's purview—amounting to ₹14,000 and ₹12,000, respectively—has been criticised as a glaring example of politically motivated populism. To justify appeasement politics based on communal lines, the Delhi government announced honorariums for Pundits and Granthis of 18,000/- month without classifying and class or section, neither giving any details of the source of funds to tackle the burden on the exchequer. The perceived lack of transparency and accountability in managing public funds has further underscored doubts about AAP's governance model and financial credibility.

AAP's economic management in Delhi is thus a complex tale of contradictions and controversies coupled with self-bolstering claims of miracles. Its populist strategies may have won public favour in the short term, aiding in garnering votes and public support from state assembly elections but they have also placed the city's fiscal health on shaky ground. The decline in revenue, rising debt, and allegations of financial mismanagement, along with corruption allegations, demand urgent course correction. Moving forward, the Aam Admi Party must transcend its obsession with optics and focus on strengthening institutions, fostering stakeholder collaboration, and grounding its policies in evidence-based frameworks to reflect some tangible outcomes. The Aam Admi Party is a party born out of the Anna-Andolan (Anti-Corruption) protest, which undermines the very essence and cardinal principles of its formation and acceptance by the public as an alternative to mismanagement of the Indian National Congress. The involvement of AAP in alleged corruption has left deep marks on people's consciousness, as now the people are not ready to accept the protests as genuine, remembering the platform that protest facilitated to a party that practised against what it stood for. Only by prioritising genuine governance over political expediency can it transform itself from a party of promises to one that delivers enduring and meaningful change. Until such a shift occurs, its legacy will remain a cautionary tale of missed opportunities and unfulfilled aspirations.

झूठे वादे और झूठे प्रचार का केजरीवाल मॉडल

अरुण राठी, पत्रकार एवं बाल्यकाल स्वंयसेवक

अरविंद केजरीवाल के वादे हमेशा खोखले साबित हुए हैं और वे उन्हें 'गजनी' की तरह भूल जाते हैं। उनकी सरकार बिना परिणाम दिए सिर्फ घोषणाएं करती रहती है। दिल्ली को खाली नारों से ज्यादा असल विकास की जरूरत है।

केजरीवाल सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे का राज्य को संभालते हैं। जिसमें ना कृषि विभाग है, ना पशुपालन विभाग है, ना मछली पालन विभाग है, न ही समुद्र तट विकास विभाग है, न ही पुलिस या न्याय व्यवस्था विभाग है, ना ही वन विभाग है, और ना ही इसके राज्य की सीमा किसी दूसरे देश से लगती है, दिल्ली में एकमात्र नदी है यमुना जो एक नाले से भी बदतर है यानी इसे नदियों का विकास काम भी नहीं देखना है। केजरीवाल को सिर्फ डीटीसी बस चलाना है और 12 वीं तक का शिक्षा व्यवस्था देखना है और मात्र इन दो विभाग पर केजरीवाल आज पूरे भारत के सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले मुख्यमंत्री बन गए है।

झूठे वादे करके मुकर जाना ही केजरीवाल जी का जीवन दर्शन है। पंजाब में 2021 में महिलाओं को ₹1000 देने का वादा किया था। आज तक नहीं दिया ।
दिल्ली में दो बार महिलाओं को ₹1000 देने का वादा किया था। एक बार भी नहीं दिया।

अरविंद केजरीवाल का दावा कि उनके पास विकास, विज़न और टीम हैं पूरी तरह हास्यास्पद है।

यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा की यह केजरीवाल का भ्रष्ट विज़न एवं टीम वर्क है की दिल्ली जल एवं वायु प्रदूषण, सड़कों - सीवर की बदहाली, चरमराई ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ एवं शिक्षा व्यवस्था का मॉडल बन गई है और इस टीम वर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि है शीशमहल एवं शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार |

शायद यह केजरीवाल के गज़ब टीम वर्क विज़न का परिणाम है की 10 वर्ष की पुरानी बातें तो छोडिए इसी वर्ष मानसून में दिल्ली की सड़कों पर जलजमाव एवं बिजली करंट लगने से 62 से अधिक निर्दोष जानें चली गईं, दिल्ली में क्लास रूम निर्माण घोटाला एवं बिना ऑपरेशन थियेटर एवं मेडिकल स्टाफ की भर्ती के अस्पताल की बिल्डिंगों का निर्माण घोटाला कर डाला, 10 साल पहले तक लगभग 500 करोड़ प्रति वर्ष का लाभांश देने वाला दिल्ली जलबोर्ड आज 70 हजार करोड़ के घाटे में है, जिस दिल्ली को 11 हजार वाली सार्वजनिक बस सेवा चाहिए वहां 5 हजार बसें चलती हैं उनमे से 3000 सी.एन.जी. बसें आज कंडम हाल में चल रही हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, देश के दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कलाइमेट फंड के इस्तेमाल के मामले में सबसे खराब स्थिति में है। रिपोर्ट ने एनसीएपी के 5 सालों के संचालन में प्रबंधन पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, एनसीएपी के तहत अधिकांश फंड को धूल नियंत्रण उपायों पर आवंटित किया गया है।

दिल्ली सरकार की अक्षमता स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के बजाय लगातार पड़ोसी राज्यों को दोषी ठहराया है। प्रदूषण स्तर इतना गंभीर हो गया है कि शहर रहने योग्य नहीं रहा है। यदि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आबंटित की गए फंड का अच्छे और सही तरह से इस्तेमाल किया होता, तो केंद्र सरकार का 2025 तक प्रदूषण में कम से कम 40 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था। इससे दिल्ली के लोग बीमारियों की चपेट में कम से कम आते और ज्यादा स्वस्थ रह पाते।

केजरीवाल का मॉडल सिर्फ झूठे प्रचार पर आधारित है। काम कम, प्रचार ज्यादा - यही उनकी नीति है। जो पैसा जनता की सुविधाओं पर लगना चाहिए था, वो पिछले 10 वर्षों में केवल प्रचार में उड़ा दिया गया।

केजरीवाल के प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है, दिल्ली में झूठे वादे और झूठे प्रचार ही असली केजरीवाल मॉडल है।

#Farjiwal के झूठे वादे

दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाएंगे	**2 लाख छात्र** अभी भी शिक्षा से वंचित
24x7 साफ मुफ्त नल से पानी सुनिश्चित करेंगे	**43% से अधिक** झुग्गी निवासी बोतलों और टैंकरों का पानी खरीदते हैं
दिल्ली को फ्री क्लीनिक और अस्पतालों का मॉडल बनाएंगे	**70% मरीज निजी** अस्पतालों में जाने को मजबूर
5 साल में यमुना को सुंदर बना देंगे	यमुना हुई पहले से भी अधिक **गंदी और बदबूदार**
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे	जानलेवा **AQI** से हर दूसरे बच्चे के फेफड़े हमेशा के लिए खराब
दिल्ली को करप्शन मुक्त प्रदेश बनाएंगे	CM, डिप्टी CM, **5** मंत्री, **1** सांसद और **10** विधायक जेल गए

AAP की #1 रैंकिंग का सच

टैंकर माफिया
भारत में सबसे महंगा पानी

स्कूल ड्रॉपआउट
भारत में नवी और ग्याहरवी कक्षा का सबसे अधिक फेलियर रेट

वायु प्रदूषण
दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी

दिल्ली देश में 1

भ्रष्टाचार
भारत के किसी भी राज्य सरकार के तुलना में सबसे ज्यादा मंत्री जेल में

कचरे का पहाड़
गाजीपुर लैंडफिल बना देश का सबसे ऊंचा लैंडफिल

जल प्रदूषण
भारत की सबसे प्रदूषित नदी

केंद्र ने दिया, केजरीवाल ने छीना

प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू न कर, **10 लाख परिवारों** का किफायती आवास का हक़ छीना

राशन कार्ड न देकर **90,000** गरीबों से मुफ्त राशन छीना

जल जीवन मिशन को लागू न कर, हर घर में नल से जल का अधिकार छीना

आयुष्मान भारत को लागू न कर, **51 लाख लोगों** से **₹5 लाख** का स्वास्थ्य कवच छीना

वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में बाधा डालकर अर्बन एक्सटेंशन रोड, RRTS परियोजना और बेहतर मेट्रो की सुविधा छीनी

PM - ABHIM में बाधा डालकर **₹2400 करोड़** से भी अधिक लागत वाले स्वास्थय इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को छीना

खुद के लिए बनाया करोड़ों का शीशमहल

ऑटोमैटिक दरवाजे
₹70 लाख

साज - सज्जा
₹10 करोड़

फ्रिज
₹9 लाख

वियतनामी मार्बल
₹1.15 करोड़

कारपेट
₹50 लाख

1 कमोड
₹10- ₹15 लाख

बॉडी मसाज चेयर
₹4 लाख

परदे
₹5 करोड़

कुल कीमत
₹52 करोड़

6 रेवड़ी देकर 12 रबड़ी खुद हजम की

- **शराब नीति घोटाला:** नवंबर 2021 में लागू की गई नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने **करोड़ों की रिश्वत** लेकर चुने हुए शराब माफियाओं को लाइसेंस बांटे। घोटाला उजागर होने के बाद नीति को तुरंत वापस ले लिया गया।
- **दिल्ली जल बोर्ड घोटाला:** 2015-2023 के बीच दिल्ली जल बोर्ड को **₹28,400 करोड़** आवंटित किए गए, लेकिन पानी और सीवर परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय AAP नेताओं ने अपनी जेबें भर लीं।
- **क्लासरूम घोटाला:** AAP सरकार ने **7,137 क्लासरूम** के लिए भुगतान किया, लेकिन केवल 4,027 क्लासरूम बनाकर **₹1300 करोड़ रुपये** का घोटाला किया।
- **मोहल्ला क्लिनिक घोटाला:** AAP सरकार ने **65,000 फर्जी टेस्ट** दिखाकर सरकारी खजाने से करोड़ों लूटे और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया।
- **बसों में पैनिक बटन घोटाला:** AAP सरकार ने बसों में पैनिक बटन लगाने के नाम पर **₹500 करोड़** का घोटाला किया, जिसमें बिना किसी कंट्रोल सेंटर के यह योजना फर्जी साबित हुई।
- **CCTV कैमरा घोटाला:** महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर **₹571 करोड़** का घोटाला करते हुए AAP सरकार ने फर्जी प्रोजेक्ट चलाया।
- **राशन वितरण घोटाला:** घर-घर राशन पहुंचाने के नाम पर AAP सरकार ने **₹5400 करोड़** की चोरी की।
- **टैंकर माफिया खत्म करने का वादा:** टैंकर माफिया को हटाने का वादा करने वाली AAP के शासन में **टैंकर माफिया** और ताकतवर बन गया।
- **शीशमहल:** अरविंद केजरीवाल ने 8 सरकारी बंगले तुड़वाकर खुद के लिए 50,000 गज का शीशमहल बनवाया और जनता के ₹52 करोड़ रुपये उड़ा दिए।
- **वक्फ बोर्ड घोटाला:** दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने **₹100 करोड़** की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया और अवैध नियुक्तियां की।
- **DTC बस घोटाला:** 1,000 नई बसों को खरीदने के नाम पर AAP सरकार ने **₹4500 करोड़** का घोटाला किया।

Delhi: मोहल्ला क्लीनिक फर्जीवाड़ा केस, 2 लैब्स ने किए 65 हजार 'Ghost' मरीजों के टेस्ट

"Ad Man" केजरीवाल: AAP सरकार ने सिर्फ 3 साल में विज्ञापनों पर जनता के ₹1,073 करोड़ से अधिक रुपये उड़ा दिए।

घोटालों ने की करोड़ों की अस्पताल परियोजनाएं ठप

- **₹5,590 करोड़** का बजट आवंटित किए जाने के बावजूद 24 प्रस्तावित अस्पतालों में से ज्यादातर अस्पताल सिर्फ कागज पर मौजूद हैं। साथ ही, **38,000 डॉक्टर,** विशेषज्ञ और पैरा-मेडिकल स्टाफ के पदों को न भर AAP सरकार ने युवाओं को रोजगार और जनता को अच्छे इलाज से दूर रखा है।
- AAP सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते केंद्र की PM-ABHIM योजना के तहत **₹2400 करोड़** से बनने वाले 1,139 स्वास्थ्य केंद्र, 11 लैब और 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स से दिल्लीवासियों को वंचित कर दिया।
- ₹1125 करोड़ की लागत से 7 आईसीयू अस्पतालों का निर्माण 6 महीने में होना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा है और ठप पड़ा है। देरी के कारण लागत बढ़कर ₹2250 करोड़ हो गई, जिससे जनता के ₹800 करोड़ बर्बाद हुए।
- AAP सरकार ने बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले केंद्रीय सरकार के हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर **(HIMS) को लागू करने से इनकार किया।**
- AAP सरकार की लापरवाही के कारण ₹465.52 करोड़ की लागत से बनने वाला LNJP अस्पताल का नया ब्लॉक, जिसकी समय सीमा 30 महीने थी, 4 साल बाद भी केवल 60% पूरा हुआ। अब इसकी लागत बढ़कर ₹1125 करोड़ हो गई है, जो सरकार की अक्षमता और जनता के धन की बर्बादी को दर्शाता है।
- दिल्ली सरकार ने 94 पॉलीक्लिनिक के नवीनीकरण के लिए ₹168.58 करोड़ का ठेका दिया था, लेकिन PWD ने इनमें से केवल 52 पॉलीक्लिनिक में भी आधा-अधूरा काम किया। इस लापरवाही के चलते संशोधित लागत बढ़कर ₹220 करोड़ तक पहुंच गई। AAP सरकार ने इस तरह जनता के पैसों की खुली लूट की है।
- दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में घोटालों की सूची बहुत लंबी है:
  - **फर्जी मरीजों** का रिकॉर्ड
  - **फर्जी मेडिकल** टेस्ट
  - **डिजीटाईजेशन और सही प्रबंधन की कमी** के कारण, दिल्ली का हेल्थकेयर सिस्टम पूरी तरह से ढहने की कगार पर है।
  - **नकली दवाइयां**
  - दवाइयों और टेस्टिंग सुविधाओं की कमी

"दिल्ली का GTB अस्पताल

The Indian EXPRESS

'हमें दवाइयां उधार लेने की नौबत आ गई है': मोहल्ला क्लीनिक, जो कभी AAP सरकार का मुकुटमणि हुआ करते थे, अब आवश्यक दवाओं से वंचित हो रहे हैं

AAP के फर्जी शिक्षा मॉडल की सच्चाई के तथ्य

- हर वर्ष AAP सरकार द्वारा कक्षा नवी और ग्याहरवी में **1 लाख 50 हजार** छात्रों को फेल किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, AAP सरकार फेल हुए छात्रों को फिर से एडमिशन की अनुमति नहीं दे रही है जिस कारण छात्रों के शिक्षा के सपने बिखर गए हैं।
- दिल्ली सरकार के कुल 1043 स्कूलों में से 753 स्कूलों में साइंस विषय नहीं पढ़ाया जाता, जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है।
- **नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) 2017** के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्कूलों के कक्षा 3 और कक्षा 5 के छात्रों का प्रदर्शन गणित, पर्यावरण विज्ञान और भाषा में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे था।
- AAP सरकार द्वारा बनाई गई **स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी** का वादा केवल कागजों पर दिखा हकीकत में नहीं।
- दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। यह यूनिवर्सिटी वर्तमान में केवल दो स्कूलों की कक्षाओं में संचालित हो रही है, और उसमें मात्र 12 छात्र नामांकित हैं।
- भारी विज्ञापनों के बावजूद, **दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU)** में नामांकन बेहद कम रहा एवं 60% से अधिक सीटें खाली हैं जिस कारण विश्वविद्यालय को प्रमुख **एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स** को बंद करना पड़ा।
- रोहिणी सेक्टर-18 में अथक प्रयासों से स्थानीय बच्चों के लिए बनाए गए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिले पर अचानक रोक लगा दी गई। 2023-24 सत्र में **2500 बच्चों के दाखिले की जगह** इसे "स्कूल ऑफ एक्सीलेंस" का नाम देकर केवल 200 बच्चों को दिल्ली के अन्य हिस्सों से लाकर भर्ती कर, क्षेत्र के बच्चों को उनके **शिक्षा के अधिकार से वंचित** किया गया।

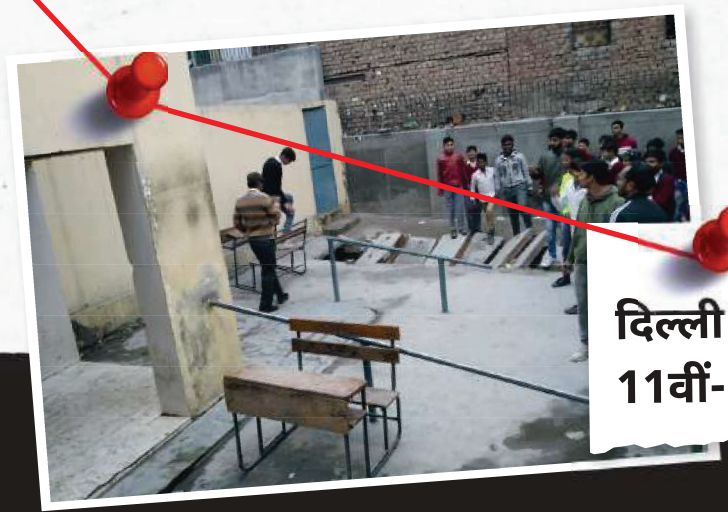

THE ECONOMIC TIMES

दिल्ली के दो तिहाई सरकारी स्कूल 11वीं-12वीं कक्षा में विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं

वेबसाइट देखने के
लिए यहां स्कैन करें

10 साल दिल्ली बेहाल

आपका एक वोट
धोखेबाजों को चोट
दिल्ली चली
भाजपा के साथ

आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक

अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे